SHRl N. K. P. SALVE: You^ were wearing it in protest. We are wearing our party badge; it is not in protest and it is not any disrespect to ihe Chair *o:* to the House. *(In-terruptions).*

THE DEPUTY CHAIRMAN: By convention if Members do not wear badges, it is belter. *(Interruptions).*

SHRI V. GOPALSAMY: On a point of order. *(Interruptions).*

[Mr. Chairman in the Chair.J

SHRI N. K. P. SALVE: My point of order may be heard, Mr. Chairman, An lion. Member raised objection that some Members have come into the Chamber wearing the Centenary badges of the Congress party. He stated that on principle he does not want that to happen. My respectful submission is that the Member said that this is in violation of the Rules. I think, as far as I know, there is no rule which prohibits a badge being worn which is. not in protest against the proceedings in the House or any other protest as such or which is not in any manner meant to show disrespect to the Chair. My respectful submission, therefore, is that a Member wearing a badge and entering the Chamber is neither violating the Rules nor violating a convention. A non-issue must not be raised *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: T will give my ruling. *(Interruptions)* Now, there is no rule that a person should not wear any badge or anything like that in the House! But it has been our convention that people do not come into the House with badges Now. when I came by some inad-vertance with a NAM badge in the House, which had nothing to do with anything, the Speaker said: You must observe the convention. And I took it away-. *(Interruption* in the House that we do not wear badges of any kind. *(Intei-tions).* Therefore, it is a convention in the House that we do not wear badges of any kind. *(In-terruptions).* Please take this as a. . . *(Interruptions).*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASOKE KUMAR SEN): Sir, when Mr. Pi loo Mody came to the House with a badge "I am a CIA Agent" ---------- *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: And it was violently objected to.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: He ultimately took it away.

MR. CHAIRMAN: That is why, as T said, there is a convention in the House that people do not wear any badge. Let us observe the convention.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Kalp Nath Rai is also weeing. .

MR. CHAIRMAN: All Congress Members, please take awav your badges when you come from the Centenary. One need not go into any controversy over this. Now you go to the Discussion.

tThe Deputy Chairman in the Chair.1

DISCUSSION ON THE WORK-ING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND PURAL DEVELOPMENT

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : माननीया, हम लोग आज कृषि मंत्रालय के कार्यों पर बहस करने के लिये यहां इकट्ठे हुए हैं । जिन मुल्कों में तरक्की की रफ्तार बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, फैशन बढ़ता है, दुनिया की जानकारी आती है, उन मुल्कों के

नेतृत्व की बुनियाद में कमजोरी हो जाती है। वह कृषि को गंवार लोगों का, जाहिल लोगों का, दूसरे दर्जे का काम समझते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का फख्र है कि परसों हमारे पार्टी की जो बैठक थी ए० आई०सी०सी० की, उसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि के बारे में जितना समय दिया, उतना किसी और मुद्दे के लिये नहीं दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार कृषि के महत्व को समझती है और समझती रहेगी।

माननीया, मैं एक पश्चिमी विद्वान की किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि दुनियां के बहुत से वैज्ञानिक कृषि को विज्ञान मानने के लिये तैयार नहीं हैं। जबकि सही बात यह है कि खेती विज्ञान की मां है, जिसको मदर साइंस कहियेगा, वह खेती है। आदमी का अस्तित्व, आदमी की जीविका, आदमी का जिंदा रहना खेती के ऊपर निर्भर है। एण्ड और जनुअश, जो विद्वान हैं, इन्होंने अपनी किताब में आखिर में लिखा है—दुनिया में साइंस की तरक्की सही थी या गलत थी, यह खेती के सफल होने या असफल होने से तय होगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज है—खेती।

आजाद देश होने के बावजूद हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के कृषि वैज्ञानिकों ने, सरकार ने बहुत से बेमिसाल काम खेती के क्षेत्र में किये हैं। हमारा जो पिछले साल का उत्पादन है, वह 1515 मी० लाख टन है, जो वर्ष 1981–82 साल के अधिकतम उत्पादन से 182 मी० टन ज्यादा है। तीन गुने के करीब हमने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया है और बहुत से मामलों में तो छह गुना तक बढ़ाया है, जिसके लिये इस देश के किसानों को बधाई दी जानी चाहिये। इस देश के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वे तारीफ के काबिल हैं और बहुत सी जगह तारीफ हुई भी है। लेकिन सिर्फ अच्छे बीज और अच्छी खाद और किसान की मेहनत से ही नहीं बल्कि शुरू में आजादी के फौरन बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो विज्ञान के लिये का कार्यक्रम बनाए, ब्लाक्स बनाए और मुझे याद आता है गुन्नार मिरडल ने एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तान की प्लानिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री चाहे जिस मौके पर बोले, वह जवाहर लाल जी का जिक्र कर रहे थे, वह प्लानिंग में किसान और मजदूर के बारे में जरूर बोलते हैं। तो उस समय भी व्यापक कार्यक्रम विकास के बने और इसके कारण इतनी तरक्की हुई।

जब इंदिरा जी का राज आया। उस वक्त दुनियां की एक बड़ी ताकत इस कोशिश में थी क्योंकि थोड़ा सा हम अनाज के मामले में कमजोर थे। कोशिश हुई कि कैसे इनके हाथ ऐंठे जाएं, हाथ मरोड़े जायें। लेकिन अमरीका से वापस आने के फौरन बाद पहला काम यह किया कि देश को अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बनाने की कोशिश की और पांच-सात साल के अरसे में देश के पूरे भण्डार खाद्यानों से भर गये।

इन बातों का जिक्र किए बगैर अगर मैं यह सोचता हूं कि आगे के लिए क्या करना है, तो यह किसानों के साथ हमारे नेताओं के साथ, कृषि वैज्ञानिकों के साथ और विस्तार कार्यक्रमों के साथ, विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रालय या कृषि विभागों के साथ व उससे सम्बन्धित लोगों के साथ ज्यादती करूंगा। है। यह बड़ा भारी एचीवमेंट है और सारी दुनियां ने इसको सराहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के लिए भी इसके लिए जितनी फौज जरूरी है, जितनी परमाणु ऊर्जा जरूरी है, इसके लिए जितनी बिजली जरूरी है देश के लिए जितने खजाने जरूरी हैं, उसमें सबसे मूलभूत जरूरत हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने की है। हमारी विदेश नीति, हमारा रोबदाब सब कुछ निर्भर करेगा इस चीज पर कि हमारे पास खाने के लिए अनाज है या नहीं। इस लिहाज से देखें तो दो हजार ए० डी० तक हमको बहुत ज्यादा अनाज की जरूरत होगी करब 230 मिलियन टन अनाज की जरूरत होगी यानी जितनी हमने उपलब्धि आजादी के बाद की हैं उतना ही और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तब हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पिछली तरक्की को देखता हू, तो खुशी होती है, लेकिन जब मैं जरूरत की तरफ देखता हूं तो इस दृष्टि से बोलना चाहूंगा कि मैं बताऊं कि इन-इन चीजों की जरूरत है और वे नहीं हो रहीं।

[श्री सत्य पाल मलिक]

अब मैं इस तरफ आना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए। इस सारी तरक्की के बावजूद सच यह है कि कुछ फसलों में उत्पादन में स्टेगनेशन आया हुआ है । कुछ चीजों का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया है । आप चाहें तो दालों को ले लीजिए। दालों में 40 प्रतिशत चने का इस्तेमाल होता है । चने के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायी है । तिलहन का यही मामला है । पिछले सालों में कपास और जूट का उत्पादन गिरा है, बढ़ नहीं रहा है यह चिन्ताजनक बात है । जब चने का, मोटे अनाज का उत्पादन कम होता है तो उसका नुकसान हमको उतना नहीं होता जितना देश के सबसे गरीब आदमी को होता है, फैट्स उसको उपलब्ध नहीं हैं, मांस, अंड़ा, मछली उपलब्ध नहीं है। उस गरीब आदमी को सारा न्यूट्रीशन दाल से मिलता है, लेकिन दाल उसके लिए अनुपलब्ध है, महंगी है जिन चीजों में चावल और गेहूं की तरह ब्रेकथ्रू नहीं हो पाया है उस तरफ ताकत लगानी चाहिए । अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा किए जायें और दुनियां में जो सबसे बेहत्तर टैक्नालाजी है उसको लाया जाये । हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनके उत्पादन को बढ़ायें ।

जिन चीजों में स्टेगनेशन है वे हमारे विए सार्वाधिक चिन्ता का विषय है । इसके अलावा एक खतरनाक बात यह भी हुई है कि जिस तरह उद्योग में असमानता है, कहीं बहुत ज्यादा उद्योग हैं, कहीं बिल्कुल नहीं, एक तरफ दिल्ली के आसपास फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाके है जहां उद्योगों का जबरदस्त कन्सेट्रेशन है, दूसरी तरफ जहां से मैं आता हूं, दिल्ली से उतनी ही दूर है जितना फरीदाबाद और गाजियाबाद, लेकिन आज भी वहां कोल्हू और ईंट के भट्टे से बड़ा कोई उद्योग नहीं है इसी तरह कृषि के मामले में बहुत जबरदस्त असमानता देश में हुई । एक-एक चीज को आप लें—क्राप्ड एरिया इरीगेटिड—'77 तक के आंकड़े हैं—बिहार में 31.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11.2 प्रतिशत, उड़ीसा में 19.2 प्रतिशत पंजाब में 18.8 और तमिलनाडु में 12 प्रतिशत । फर्टिलाइजर बिहार में किलोग्राम पर हेक्टेयर 16, महाराष्ट्र में 185, पंजाब में 76.7, तमिलनाडु में 64.1 और पूरे भारत का एवरेज 26.2 प्रतिशत । इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो छोटे किसानों को मिलती है—रुपये पर हेक्टेयर—बिहार 47, महाराष्ट्र 175, उड़ीसा 75, पंजाब 273, तमिलनाडु 341 और पूरे भारत का औसत 134 । इसी तरह प्रति एकड़ उपज और प्रति एकड़ इनपुट की लागत है उसमें भी इसी तरह की असमानता बनी हुई है । तो कोशिश होनी चाहिये कि इस असमानता को दूर करके कृषि की व्यापक नीति तैयार की जाए क्योंकि इसी के साथ किसान के साथ-साथ दीगर पेशों के ग्रामीण भी जड़े हुए हैं । तो इस असमानता को ध्यान में रखना होगा । और इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिटाना होगा । खेतों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजों का जरूरत है । उस के लिए सिंचाई की जरूरत है, खाद की जरूरत है, अच्छे बीज की जरुरत है, कर्जों कीं जरूरत है, दवाइयों की और सर्विसेज की जरूरत है, सारे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की जरूरत है । लेकिन इन सारी चीजों पर आने से पहले जो मूल चीज है जिससे खेती का भविष्य तय होने वाला है, जिसकी कमी की वजह से कई बार उत्पादन में गिरावट आती है मैं सबसे पहले उस चीज को लेना चाहता हूं और वह है कृषिकी पैदा की हुई चीजें हैं उनके दाम की नीति मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के चुनाव के दौरान और उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री ने नीति वक्तव्य के दौरान और बजट के दौरान हमारे वित्त मंत्री जी ने बार-बार इस बात को दोहराया कि हम कृषि अन्य पदार्थों क जो मूल्य नीति है उसमें मूलभूत परिर्तन करेंगे और मैं उनको उस बात के लिये बधाई देता हूं कि पहली बार उन्होंने कृषि मूल्य आयोग के चरित्र को बदला है उसको बढ़ाने की बात हुई है । उसमें किसानों के नुमाइन्दों को ज्यादा बढ़ाने की बात हुई है । यह बहुत संतोष की बात है । लेकिन इस देश के जो अर्थ-शास्त्री हैं, इस देश के जो कृषि अर्थ-शास्त्री हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो खास कर शहर वर्ग से आये हुये लोग, उन्होंने बहुत खतरनाक बहस कृषि पदार्थों के मूल्यों के बारे में

चलायी है। देश में यह बहस चलायी गयी है कि किसान की फसल का दाम अगर बढ़ाया गया तो महंगाई बढ़ेगी। इससे ज्यादा एब्सर्ड और बेहूदा बात कोई और हो नहीं सकती। मैं इस को दलील के साथ कहना चाहता हूं। यह बिलकुल गलत बात है। इस समय सारी दुनिया में, माइकेल लिपटन की एक किताब आयी है "पुअर पीपुल रिमेन पुअर", उसमें और मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कृषि मूल्यों के बारे में है और उसे पढ़कर मुझे बड़ी शरमिंदगी हुई। उसमें कहा गया है कि बाजार में जो दाम हैं– उन्होंने सारी दुनिया के एक सौ कुछ मुल्कों का जायजा लिया है जिसमें पेरू को छोड़ कर जो कि एक बहुत ही इनसिगनीफिकेंट देश हैं, नम्बर दो पर हिंदुस्तान है जहां कि टर्म्स आफ ट्रेड सबसे ज्यादा किसानों के खिलाफ जाते हैं। जो चीज वह पैदा करता है और जो चीज वह खरीदता है उनमें जिस हिसाब से फर्क है वह अभूतपूर्व है। ऐसा दुनिया के बहुत कम मुल्कों में होता है। सरकार कितनी ही नेकनियती से कोशिश करे वह किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं दिलवा सकती। अगर आप 1970–71 के वर्ष को सौ मान लें तो फर्टिलाइजर आज 273 है और यह दो साल पहले के आंकड़े हैं जो ए.आई.सी.सी. के कैंप के बाहर एक किताब बिक रही थी उसमें से मैं देख पाया हूं। उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट प्राइस आज 171 है और डिजिल 1970–71 की बेसिस पर अगर उसे 100 मान लें तो वह आज 732 है। किसान जितनी चीजें खरीदता है, जिस में कपड़ा है, लोहा है डिजिल है, ट्रैक्टर है, इन सारी चीजों के दाम जिस हिसाब से बढ़े हैं उसको देखते हुए जिन चीजों को वह पैदा करता है उनके दामों में एक जबरदस्त अन्तर है। और इसका नतीजा होता है कि उस किसान की जो खरीदने की ताकत है वह कम होती जा रही है और जब उसकी ताकत कम हो रही है तो उसकी जमीन पर लगे हुए मजदूर की ताकत कम हो रही है। जो शहरी अर्थ-शास्त्री है वह यह दलील देता है कि अगर अनाज मंहगा हो गया धरती से पैदा होने वाली चीजें मंहगी हो गयी तो सब से गरीब आदमी मर जाएगा। यह बिलकुल बेबुनियाद तर्क है। वह तो सब से गरीब आदमी है। अक्सर वह मजदूरी काइंड में लेता है, कैश में नहीं। वह अनाज लेता है मजदूरी के एवज में, नकद नहीं लेता। नम्बर दो; जो सारा सिस्टम अनाज को प्रोक्योर करके बांटने का है उस में सब से गरीब आदमी को क्या वह अनाज मिलता है। यह तो शहर के वोकल सेक्शन को, शहर के ताकतवर सेक्शन को मिलता है और उस गरीब खेत मजदूर को नहीं मिलता। अगर आप दावा करें कि गांव के सब से गरीब आदमी को जिस के पास जमीन नहीं है, हम यह अनाज देंगे तो किसान इस बात के लिए तैयार है कि किसान कम दाम पर अनाज देगा। लेकिन अकेले किसान ही क्यों देगा? फिर तो जो सारे देश का रेवेन्यू है उस में से सब्सीडी दी जाये और उस में सब से गरीब आदमी का भी हिस्सा हो, व्यापारी का भी हिस्सा हो, टेक्नीशियन्स का भी हिस्सा हो, सरकारी कर्मचारियों का भी हिस्सा हो और वकीलों का भी हिस्सा हो और किसान का भी हिस्सा हो। अकेले सब से गरीब आदमी को खिलाने का तर्क बिलकुल बेहूदा तर्क है। किसान यह नहीं कहता कि उसको उस की फसल का दाम अनाप-शनाप दिया जाये। आप तय कर लीजिए समता मूल्य का सिद्धांत। जिस हिसाब से उसको चीजें दी जायेंगी, जिस हिसाब से उनके दाम बढ़ें उसी हिसाब से आप तय कर लीजिए। जब दाम तय होते हैं, तो समता मूल्य के सिद्धांत के हिसाब से तय नहीं होते। जब चौधरी चरण सिंह की सरकार आयी थी तो समझा जाता था कि बहुत बड़ी बातें हुई थीं। परन्तु मुझे जान कर हैरत हुयी और आडवाणी जी चले गए, मैं इस बात की उन से गवाही दिलाना चाहता था कि जनता सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी दिन के लिए दाम के मामले पर बहस नहीं हुई जब कि गन्ना 3 रुपए और 4 रुपए क्विंटल बिका और आलू दस रुपए मन और आठ रुपए मन बिका। लेकिन कोई नोट आफ डिसेंट चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल से नहीं हुआ। इस पर कोई बहस नहीं हुई और जो सारी उपलब्धियां जनता सरकार बताती है कि हम ने दामों पर नियन्त्रण रखा वह किसान की उपज की कीमत पर रखा गया। शहर में उत्पादित चीजों के दाम बढ़े और किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम कम हुए। बिरला जी की कार 27 हजार की बिक रही थी जब मोरार जी देसाई

[श्री सत्य पाल मलिक]

शपथ ले रहे थे और जब मोरारजी देसाई अपना सामान उठा कर सरकार से जा रहे थे तो वही कार 76000 की हो गयी थी। तमाम जो चीजें कारखानों में बनती हैं उनके दाम बेतहाशा बढ़े, लेकिन किसानों की चीजों के दाम नहीं बढ़े, बल्कि गिरे।

पैरिटी आफ प्राइस का जो फारमूला मंत्रिमंडल में इंदिराजी पास कर गई थीं, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसको लागू करे इसके बिना न किसानों का लाभ हो सकता है, न गांवों का विकास हो सकता है, न कोई तरक्की वहां हो सकती है। जब फसल का दाम बढ़ेगा तो उससे मजदूरी भी बढ़ेगी, ज्यादा मजदूरी मिलेगी। फसल का जब दाम बढ़ेगा तो वहां और भी विकास हो सकेगा। अभी तक वहां पर गवर्नमेंट का एक भी हायर सैकेंडरी स्कूल नहीं है। एक भी बड़ा अस्पताल वहां पर नहीं बनाया गया। कोई कालेज गवर्नमेंट ने वहां नहीं बनाया। सड़कें वहां पर नहीं बनाई। जितनी भी सड़कें पिछले 25 वर्षों में बनाई गयी हैं वे किसानों ने अपने पैसे से बनाई। किसानों के चन्दे से वहां पर स्कूल बने, अस्पताल बने। इस तरह से अगर फसल का दाम वाजिब किसान को दोगे तो वह रुपया वहीं के विकास के लिए खर्च हो सकेगा, मजदूरों को इससे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। किसानों की मनोवृत्ति यह होती है कि उसके पास जब रुपया होता है तो वह सबसे पहले इनपुट्स के ऊपर उसको खर्च करता है। बीवी की धोती बाद में आएगी, पहले खाद ले आएगा। उसकी आमदनी प्रोडक्टिव है, उसके पास जो पैसा आता है वह प्रौडक्टिव कामों पर खर्च होता है जब कि कारखाने वालों का पैसा अय्याशी पर खर्च होता है। इसलिये दाम की नीति तय हो। उत्पादन व्यय और जीवन निर्वाह व्यय को भी उसमें जोड़ा जाए। अभी का रिस्क फैक्टर जो है वह उसमें नहीं जुडना है। सूखे से, बाढ़ से जो विनाश फसल का होता है, अभी पाइरेला से सारा गेहू खत्म हो गया, उसको आप नहीं जोड़ते हैं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर विचार करेंगे। तो इसको भी आप उसमें जोड़ने लगे तो इससे किसान को जबरदस्त राहत मिलेगी। जो दाम निर्धारण का काम है वह एक खतरनाक प्रक्रिया है जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा।

श्रीमन, जो सपोर्ट प्राइस तय की जाती है, यह कोई आदर्श प्राइस नहीं है। सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि अगर उत्पादन अधिक हो गया और किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है तो आप बाजार में उस दाम पर उसका सामान खरीद लेंगे ताकि उसको नुकसान न हो। लेकिन प्रेक्टिकल में क्या हो रहा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। गेहूं की फसल आने से पहले, मिसाल के तौर पर अगर गेहूं का भाव इस समय 300 रुपये बाजार में है और आपने पौने-दो सौ रुपये तय किया है, जो ऐसी मार्केट कंडीशंस तैयार की जाएगी कि पन्द्रह दिन के अन्दर मजबूरन जो आपकी मीनियम सपोर्ट प्राइस है, उससे कम दाम पर किसान को गेहूं बेचना पड़ेगा। अगर सोनीपत में पौने तीन सौ रूपये में गेहूं बिकता है और दिल्ली में 300 रूपये उसके मिल सकते हैं तो आप चुपचाप ऐसी पाबन्दी लगा देंगे, रिटन या जबानी तौर पर जिससे वह यहां अपने गेहूं को बेच नहीं सकेगा। वह तामिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अपने गेहूं को नहीं ले जा सकता है। तो ये सारी पाबंदियां इस नाम पर लगाई जाती है कि जो प्राइवेट व्यापारी हैं वे जखीरेबाजी कर लेंगे। अगर जखीरेबाजी करें तो उसका इंतजाम है, वह आप करें। लेकिन किसान को तीन सौ रूपये मिलने की संभावना हो तो 15 दिन में एक तरह से बाजार में इस तरह से नियंत्रण किया जाता है कि वह मीनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे अनाज को बेचने पर मजबूर हो जाता है। किसान अगर लड़की के गौने की तारीख तय करता है तो वह तब जब उसका गेहूं बिकेगा। बच्चे का दाखला करना हो, घर के कपड़े बनाने हों, कर्जा अदा करना हो तो तब वह करता है जब फसल तैयार होती है उसका दाम उसको मिलता है। नतीजा यह होता है कि जिस वक्त फसल खड़ी हुई लहलहाती है, 300 रूपये गेहूं का भाव है, वह खुश होता है, लेकिन

जब फसल काटकर बाजार ले जाता है तो 175 रूपये या 150 रूपये कीमत हो जाती है और उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है । एफ०सी०आई० वाले मंडी में नहीं पहुंचते, व्यापारियों के साथ वे मिले होते हैं किसान से कहते हैं उसका गेहूं खराब किस्म का है और किसान सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए विवश हो जाता है । वह व्यापारियों पर अनाज छोड़कर चला जाता है । तो यह जो डिस्ट्रेस सैल है, आवागमन पर पाबंदियां हैं, इसके बारे में नये सिरे से विचार होना चाहिए। जो दृष्टि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले तीन महीनों में दी है, उसके आधार पर आप नीति तय करें । उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि इन सब समस्याओं के ऊपर फिर से विचार होगा ताकि किसानों को फायदा हो सके । इसके बाद सिचाई है, खाद है । इन पर थोड़ा-थोड़ा वक्त लेकर अपनी बात खत्म करूंगा । सिंचाई में पोटेन्शल जितना था उस हिसाब से काफी सिंचाई बढ़ाई गई है । जहां-जहां सिंचाई बढ़ी है वहां फर्टीलाइजर का इस्तमाल है, उत्पादन बढ़ा है । लेकिन जो डिस्टरबिंग ट्रेंड है वह मैं कृषि मंत्री जी को बताना चाहूंगा । नहरों का जाल है जो कुछ तो आजादी के बाद बनी थी और कुछ अंग्रेजों के जमाने में बनी थी । ये नहरी सिंचाई हैं । बारिश नहीं है तो नहरी पानी दे देंगे लेकिन सघन खेती के लिये, तीन-थीन खेती के लिये, अच्छी खेती के लिये, कामर्शियल खेती के लिये नहरी सिंचाई से काम नहीं चलता । जो मैनुअल कंट्रोल है, इसमें जो सिंचाई होती है इसमें ट्यूबवैल हैं । ट्यूबवैलों से सिंचाई का काम चलता है । ट्यूबवैल की 60 के दशक में, 70 के दशक में वृद्धि हुई थी उसमें अब वृद्धि रुक गई है । डिस्टरबिंग ट्रेंड है । जितनी क्षमता आपने योजनाओं में बढ़ाई है उस हिसाब से कमांड एरिया विकसित नहीं हो पा रहा है । इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये । इसमें कुछ कोशिश हुई है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सिंचाई योजना को पूरा करेंगे । लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिये । आपने आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय की तरफ से लिखा भी है कि जो छोटी सिंचाई योजना है उनमें समय कम लगता है, लागत कम लगती है, फायदा ज्यादा होता है । जो ट्यूबवैल आपरेशन हैं वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए । इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये । इसमें किसानों को छोटी-छोटी प्रैक्टीकल दिक्कतें आती हैं । पांच हार्स पावर का एक डीजल इंजन है, बिजली से सिंचाई होने वाली है तो उसे कई बार 25 हार्स पावर का ट्रैक्टर चला कर करनी पड़ती है । इसकी उस किसान को जानकारी नहीं होती । उसके पास कई बार बिजली नहीं होती । छोटी-छोटी चीजें जो हैं, जो सेल्फ कंट्रोल्ड इरीगेशन पावर हैं उसको आने वाले दिनों में बढ़ाना चाहिये ताकि ज्यादा सघन खेती हो सके, ज्यादा उत्पादन देश में हो ।

खाद का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है । खाद जहां इस्तेमाल होती है उत्पादन वहां बढ़ा है । इसमें कोई बहस नहीं है । देश में खाद को जबर्दस्त सबसिडी सरकार ने दी है । बड़े-बड़े कारखाने बैठाये हैं । देश के किसानों को जिनको दुनियां भर के लोग रूढ़िवादी मानते थे उन्होंने माना है ये बहुत समझदार हैं । जैसी-जैसी खाद इनको देते रहे वे इस्तमाल करते रहे और उत्पादन को बढ़ाया । पिछले कुछ दिनों से किसानों को दो तरह की दिक्कतें आई हैं । एक दिक्कत यह है कि खाद की कीमत उसके अनाज के दाम के मुकाबले, कपास के दाम के मुकाबले या गेहूं के दाम के मुकाबले ज्यादा हो गई है । उसकी खरीद की ताकत कम होती जा जा रही है । उसकी वजह से खाद की खपत देश में जो बढ़ी थी इन्दिरा जी के समय में, वह जनता सरकार के समय में कम हो गई थी और अब उसको बढ़ाने की जरुरत है । मैं नहीं कहता कि हम अमेरिका के मुकाबले या रूस के मुकाबले अगले दिन चले जायेंगे । अमेरिका में खेती खेती नहीं है । खेती का बड़ा भारी बिजनैस मैनेजमेंट है और उसमें उनके पास साधन हैं, पैसा है, सारी चीजे हैं । वह ज्यादा से ज्यादा खाद इस्तेमाल

[श्री सत्य पाल मलिक]

कर सकते हैं। रूस में भी इससी तरह की बड़ी भारी संस्था है जो उसको मैनेज करती है। हमारे यहां तो मार्जीनल फार्मस को खेती करनी होती है, छोटे फार्मस को खेती करनी पड़ती है। लिहाजा उसको जितनी खाद उपलब्ध हो वह कम दाम पर होनी चाहिये। इसकी कोशिश बजट में हुई है। इसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हुई है। खाद बाहर से मंगवाई गई है और अकेले खाद पर सरकार ने सबसे ज्यादा सिबसिडी देकर प्रबन्ध किया है। मैं यह कहे बगैर बाज आने वाला नहीं हूं कि कुशिया में नेपाल और एक-दो और देश को छोड़ कर खाद का प्रति हैक्टेयर जो इस्तेमाल बढ़ा था वह कम हो रहा है। इसको रोकने की कोशिश करनी चहिए और उसको बढाना चाहिए। यह मेरा निवेदन हैं।

बीजों के मामले में यह हुआ है कि देश के वैज्ञानिकों ने तरक्की की है। वे तारीफ के काबिल हैं। इनकी दुनिया भर ने तारीफ की। सरकार और वैज्ञानिक दोनों ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन किसान जितना पिछड़ा हुआ है उसके साथ उतनी ही धोखा धड़ी हो रही है। उसको जिस तरह का बीज मिलता है उसको वह तीन साल के बाद बो नहीं सकता। उसको नकली बीज मिलता है। मिसाल के तौर पर मूंगफली के बीज को लीजिए। उसमें जो फूंगस लगी होती है वह उनको दिया जाता है। उनको बढ़िया बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने कपास का अच्छा बीज तैयार किया है। जो पद्धति है तैयार करने की उससे हमने अच्छी कपास पैदा की है।

आलू का भी बहुत अच्छा बीज हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। दुनिया के सबसे अच्छे किस्म का आलू आज हिन्दुस्तान में पैदा होता है। लेकिन जहां कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये।

जहां तक ऋण की बात है, जिस वक्त वह फसल बोता है, ट्यूबवैल लेता है, ट्रेक्टर खरीदता है या उसको तंगी होती है तब ही उसको कर्ज की जरूरत होती है। इन्दिरा जी की कांग्रेस के अन्दर जब झगड़ा हुआ था तो उन्होंने आर्थिक सामाजिक मुद्दे उठा कर एक स्टेण्ड लिया। सारी दुनिया के सामने इस मामले को रखा। जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो बड़ा हल्ला किया गया। यह कहा गया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप यह देखें कि जितने बड़े पैमाने पर हिन्दुस्तान के बैंकों ने रूरल क्रेडिट दिया है या रूरल फाइनेंसिंग किया गया हैं, वह दुनिया में अपने आप में बेमिसाल है। अमेरिका का बैंक हो या इंगलैण्ड का बैंक हो, छोटी होल्डिंग के लिए एक अपना भी कर्जा नहीं देगा क्योंकि बिजनेस के पाइन्ट से उसको इससे घाटा होता है। वह कर्जा नहीं देगा लेकिन हमारे देश में बैंकों ने इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में सार्वजनिक हित के लिए कृषि के क्षेत्र में ऋण दिये हैं वह वास्तव में बेमिसाल है। बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे दिये गये हैं। लेकिन कर्जे की शर्तें बैंकों से या दूसरे इंस्टिट्यून्स से जब आती हैं तो आते-आते उसकी दरें बहुत बढ़ जाती है। किसानों से उस कर्जे को वसूल करने में भी दिक्कतें होती हैं। मैं मनानीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अब फसल बीमे की योजना शुरू की है। यह योजना किसान को परपेचुअल संकट से छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करेगी। फसल अगर बेहतर नहीं होगी तो ऋण अदायगी इश्योरैंस कम्पनी की तरफ से होगी। यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें बहुत मामूली चीजें है। हमारे वित्त मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि दो, ढाई हजार करोड़ रुपया आज देश का बड़े आदमियों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का पड़ा हुआ है। वे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये हैं। इसका फैसला होने में दस साल लग जाएंगे। कानून में उनकी गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। इनकम टेक्स के लिए आपने प्रावधान किया है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। यह आपने बढ़िया काम किया है कि सम्पत्ति कर या इनकम टैक्स की अगर कोई चोरी करता है उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक

काम और आप कर दीजिये। कलम की एक नोक से आप इसको कर सकते हैं। दोनों सदनों में एक मिनट में वह पास हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसान कर्जा लेता है। जिस वक्त वसूली का वक्त आता है उस वक्त 50 रु० या 150 रु० या 200 रु० की एवज में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप उसका खेत रहन में रख लेते हैं, ट्रैक्टर भी रहन में रखा होता है, नीलामी हो सकती है, लेकिन उसका अफसर जाता है वह मात्र 100 रु० की एवज में गांव के चौधरी जिनके मुद्दतों से गांव में रोजी-रोटी के फैसले होते हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी में एक भी बेईमानी का काम नहीं किया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको बंद किया जाना चाहिये। उस किसान के लिये सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात होती है। आपका अफसर उसकी इस सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है इसलिये मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जे के मामले में किसान की गिरफ्तारी को तुरन्त एबालिश कर दिया जाय। मैं उन लोगों में से हूं नहीं जो यह कहते हैं कि किसान को कर्जे की अदायगी नहीं करनी चाहिये। हमारे विरोधी दल के नेता यहां पर बैठे हुये हैं। हरियाणा में पिछले चुनावों में यह कहा गया कि किसान जो कर्जे लेता है उसको माफ कर देना चाहिये .. (व्यवधान) जो लीडर किसानों से यह कहते हैं कि वे कर्ज वापस न करें किसानों के दुश्मन हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को कर्जा वापस देने की आदत डालनी चाहिये। उसका ब्याज कम हो, उसकी दिक्कत कम हों, यह तो ठीक है, लेकिन किसानों से यह नहीं कहना चाहिये कि तुम अपना कर्जा वापस मत करो। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसानों की गिरफ्तारी कर्जे की एवज में बिलकुल नहीं होनी चाहिये। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसा प्रस्ताव लायेंगे तो वह दोनों सदनों में पास हो जाएगा।

बीज के मामले में मैं बता चुका हूं। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे हरियाणा में एक कीड़ा 'फड़का' या फायरला लगा हुआ है। किसान अगर उसको एक खेत में मारता है तो दूसरे खेत में तीसरे खेत में चला जाता है और इस तरह से फसल को बर्बाद करता है। किसान के पास कोई मशीन नहीं है। मशीन का रख-रखाव वह नहीं जानता है। दवायें बहुत मंहगी हैं और उन मंहगी दवाओं में भी मिलावट है। ऐसे मौके पर अगर एग्रो सेवायें सस्ते दाम पर प्राइवेटली या सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जायें तो इससे किसानों को लाभ पहुंच सकता है मैं चाहता हूं कि सरकार को तत्काल इस मामले में इन्टरवीन करना चाहिये और किसानों को मदद करनी चाहिये। डीजल और ट्रैक्टर के बारे में बता चुका हूं। किसानों के बच्चों को ट्रैक्टर चलाने की ट्रैनिंग नहीं होती है। ट्रैक्टर वैसे भी सबसे ज्यादा मंहगा मिलता है वह किसान खरीदता है। एक तरफ आपने देखा कि किसान जो चीजें पैदा करता है, जैसे उसने कपास पैदा की तो जनता सरकार के दौरान उसको एक्सपोर्ट नहीं करने दिया गया और मार्किट में कपास के दाम ज्यादा न मिल जाये, इसके लिये बाहर से कपास मंगाई गई। किसान को फरीदाबाद की दो कौड़ी का ट्रैक्टर 80 हजार रुपयों में खरीदना पड़ता है और चूंकि किसान के लड़के को ट्रैक्टर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिये तीन साल में खुलने वाला ट्रैक्टर छः महीनों में खुल जाता है। उस पर किसान का 10 हजार रुपये खर्चा आ जाता है।

नतीजा यह होता है कि ट्रैक्टर के मामले में कर्जों की अदायगी इसलिये नहीं हो पाती है कि वे बेचारे जिसको उन्होंने कर्ज की अदायगी में देना होता है वह रिपेयर पर खर्च हो जाता है। डीजल पम्पिंग सेट डिफेक्टिव बन रहे हैं, डीजल में मिलावट करते हैं, जिस प्रकार लोग दवाओं में मिलावट करते हैं जो जिसके हाथ में आ गया वह मिलावट करता है, उसी प्रकार डीजल में भी मिलावट करते हैं। यह जो छोटी-छोटी चीजें हैं इनमें सुधार करके एग्रीकल्चरल सर्विसेज का डेवलपमेंन्ट करना चाहिये बहुत ज्यादा ताकत के साथ ये सब बातें कहने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी से जो खेती का नुकसान जनता सरकार के दौरान

[श्री सत्यपाल मलिक]

हो गया था उस नुकसान से पिछले 5—6 सालों में खेती के मामले में देश उबर रहा है, किसान उससे बाहर निकल रहा है। इस देश के किसानों ने साबित कर दिया है कि वह प्रोग्रेसिव हैं और वे अपने कामों को वैज्ञानिकों और नेताओं से बेहतर जानते हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों को जो राहत दी है, प्रधान मंत्री जी ने अब तक जो ज्यादा से ज्यादा समय इस पर लगाया है उसको रोशनी में रखते हुये हमें दाम नीति और ऐसे सारे मामलों पर नये सिरे से विचार करना चाहिये और इन तमाम चीजों को सही करना चाहिये तभी हम जो पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना था, ग्राम विकास का गांधी जी का जो सपना था, इंदिरा जी का जो सपना था उसको पूरा कर सकेंगे और आने वाले वक्त में अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। हिन्दुस्तान अब यह सोच रहा है कि वह ताकतवर मुल्क हो। लेकिन यह सिर्फ मिलेट्री या फौज से होने वाला नहीं है। जब हम अपने आदमी को अन्तरिक्ष में भेज आये हैं, अन्तरिक्ष क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े-बड़े नायब काम किये हैं, हमारे देश की पिछले सालों में इन क्षेत्रों में बड़ी तरक्की हुई है, हमारे देश के इंजीनियर और डाक्टर दुनिया में सब से अच्छे माने जाते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में टेक्नीशियन हमारे देश में उपलब्ध हैं, सबसे बढ़िया टैक्नीकल टैलैन्ट हमारे पास हैं इसके बावजूद हमारे बैलों से चलने वाली गाड़ी में एक लिवर न लग सके या जो रहट हैं वे पुराने तरह के हों वह ज्यादा हॉर्स पावर के न हों तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जब हमारे पास इतनी टेक्नालाजी है, हमारी टेक्नालाजी बढ़ रही है तो उसको लेकर हम गांवों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि नीति के सम्बन्ध में जो कहा है उसका समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri D. N. Barman.

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Hon. Madam Deputy Chairman, today we are discussing the working of the Ministry of Agriculture and Rural Development. In our country seventy per cent people entirely depend upon agriculture. In such a country economy cannot be built on a strong foundation unless agriculture is given its due importance. Similary, die society cannot grow on healthy lines and the democratic character of administration cannot be maintained unless agriculture is given prime importance and the land-reforms programmes are made more meaningful in the interests of agriculturists.

Madam, I would like *to* draw fee attention of the Government to certain matters. Our Party, CPI(M) and other left democratic forces have brought to the notice of the Central Government various problems associated with agriculture. But die Central Government did not give importance to what we said. I would request that representatives of the Ruling Party to consider our views on various matters deeply. I hope mat they will give special importance to agricultural programmes and land reforms in the interests of national integration and industrial development.

After independence, we present Ruling Party tried to proceed with definite objectives in regard to agricultural programmes and land reforms. Immediately after Independence, when Dr. Rajendra Prasad was the Congress President a Commission was appointed by the ruling party to fix higher ceiling on land-holdings. That Commission was known as Dr. Kumarappa Commission. It fixed higher ceiling for

*English translation of the original speech delivered in Bengali

land per family from land cultivated by one plough to land cultivated by three plougns. Implementation of land reforms was within the competence of the State Govern* ments. At that tune, all the States were being ruled by the Congress Party. Yet, no State Government implemented the recommendations of Dr. Kumarappa Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Barman, we will adjourn for lunch now. You can continue your speech at 2 o'clock.

The House stands adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock, [The Vice-Chairrnan (Shri Chimanbhai Mehta] in the Chair.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, I take this opportunity to congratulate you for occupying the Chair for the first time as Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Thank you for this expression. 1 am much obliged to the Members for having given me this opportunity to take the Chair. With your co-operation I hope to fulfil Ihe obligation bestowed upon me.

Thank you once again.

Now, Mr. Debendra Nath Barman.

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, in the context of my speech

^English translation of original speech delivered in Bengali.

made earlier, I would like to say mat no State Government implemented the recommendations of Dr. Kumarappa Commission. The then Union Agriculture Minister^ Shri Punjab Rao Deshmukh and the then Chief Minister of United Province, Shri Govind Ballabh Pant were opposed to !Iand ceiling laws. Then aim of the Ruling Party was to reform the Zamindari system by abolishing the then statutory Zamindari system. Much time and concessions were given to the big zamindars so that they might transfer surplus lands to their relatives. Even big zamindars took advantage of many loopholes in the existing laws for transferring surplus lands to their relatives.

The Ruling Party did not want to adopt such a land policy as would remove their allies in rural areas from the position of power* This policy is responsible for the concentration of land in the hands 01 tew bigt land-holders in rural areas. I would like to say something about the concentration of lands in rural areas. Three per cent of the families owning more than ten hectares of land own 26.4 per cent cultivable lands. On the other hand, vast majority of the agriculturists possessing two hectares of land own 23.4 per cent of cultivable lands. These people constitute 72.6 per cent of total number of agriculturists in rural areas. Only 15 per cent people in higher category own 51 per cent of rural wealth. Combined rural wealth for 40 per cent people in lower category comes to onlv 2 per cent. Is it the sign of national progress?

A Home Ministry Report mentions about a survey made in regard to agricultural labourers in Tamil Nadu. That survey showi

[Shir Debendra nath carman] that economic disparity has grown among agricultureses in Tamil Nadu in spue ot agricultural development tnere. Small Farmers tnere ar© unable to withstand economic pressure. They are adding to the number of landless agricultural labourers after losing then: lands. Real wages are gradually going down there.

Punjab has developed agriculturally by using nign-yieiding varieties of seeds and other modern dgri-cukural inputs. Yet the Central Government was compelled to ap-point a high-powered Committte to go into various social and economic questions that arose out of agricultural development. These consequences will be disastrous if we do not go at the root of social and economic disparities from now on. The Central Government gave some assurance to remove concentration of land and mal-distribution of wealth in rural areas. But the reality is that wealth is being con-centrated into the hands of few rich farmers in rural areas. *(Time bell rings)* It is happening because of the fact that zamindari system is being reformed instead of introducing true land reforms.

The Central Government proposed that they would introduce land reforms in the Sixth Five-Year Plan. But they postponed it. In the Seventh Plan the idea ofi land reforms was cancelled. In this context, I would like to say that Bengal is a small State. It has 4 per cent of total land in the country. It has already distributed 40 per cent of total surplus land in the country. It is being governed fey a Left Front Government. *(rime bell rings)*. It is giving primary importance to land reforms.

The Legislative Assembly of West *bvu^ai* jjiiooi^u *uic* i^uuu iveiOiiiiS Oecond Amendment) Bill. Thus Biil was sent to the Central Government tor Presidents asscat about four years ago. That Bill aas not yet been assented to by the President, it is due that Bill will not bring total land reforms in West Bengal. That Bill sought to plug the loopholes in the existing land ceiling laws which were enacted during the Congress regime. It would enable the State Govern-mem io ;ii:ipute surplus land among landlless agriculturists to some extant. Why the Central Government is not giving assent to a Bill which was passed by the West Bengal Assembly by a majority vote. I hope, the Central Government will repect democratic norm. \ again hope that tbe West Bengal Land Reforms (Second Amendment) Bill will receive the President's assent.

Green revolution was possible with the help of improved agricultural facilities, high-yielding varieties of seeds and modern agricultural inputs. In the beginning due to green revolution, there was growth in the production of foodgrains. But since 1980, the production of foodgrains per hectare has been going down. It has been mentioned in the Government report that Green Revolution reached the marginal point in 1970. Now the food grain production has come to a constant position. Why the food-grain production per hectare has been coming down since 1980? *(Tune bell rings)* The solution to this problem lies in the distribution of land free of cost to the actual tillers of the soil after parasitic Zamindari system is completely abolished in rural areas.

THE V iCii-CHAiRMAN: (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) Now please sit down.

BARMAN: Please give me two minutes.

The Central Government adopted certain programmes lute IRDP, NREP and RLDP for solving rural problems. In this connection, I would like to say tha. Budgets for IRDP and NREP in the Sixth Five Year Plan have not been idealised. Various economists and social scientists predicted that there would be annual growth of five per cent under these programmes. But actually, the growth has been less than five per cent. It was thought that under IRDP programme, one lakh fifty thousand families would be brought above poverty line every year. But for want of land reforms this target has 'hot been, fulled: rather more people have gone down bek>w poverty line. *(Time bell rings)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Please resume your seat because others have also to speak.

SHRI DEBENDRA NATH BARMAN: All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Shri Ram Chandra Vikal. Not; here Chowdhary Ram Sewak. Not here. Shri Kalnnath Rai. Not here. Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, सदन में जो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा उठाई गई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है । कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आजादी के बाद हमने कृषि के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए अनावर्त प्रयास किये हैं । इस देश हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का हमेशा ऋणी रहेगा, जिनकी रहनुमाई में कृषि के क्षेत्र में हरित-क्रांति को एक आन्दोलन के रूप में चलाया गया है और उस का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम आज तक आत्म-निर्भर हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री श्रद्धेय राजीव जी ने देश की जनता से कुछ समय पूर्व यह वायदा किया था कि खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत और अनाज उत्पादन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी । सूखे और बाढ़ के प्रकोप से निपटने का भी उन्होंने और उससे बचने का भी उन्होंने आश्वासन दिया था ।

मान्यवर, अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई है और उसके लिए एक निश्चित राशि का प्रावधान है । मैं इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव जी को बधाई देता हूं और इसके लिए साथ ही साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों, उनके सहयोगियों और किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत से हमने इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की है । लेकिन साथ ही साथ मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यहां एक और उन्होंने फसल बीमा योजना प्रारम्भ की है, वहीं दूसरी ओर पशु बीमा योजना भी प्रारम्भ करने पर वह विचार करें ।

मान्यवर, तिलहन और खाद्य के तेल की हमारे देश में काफी कमी है । अभी हमारा देश लगभग एक मिलियन टन खाद्य तेल आयात कर रहा है । स्वर्गीय प्रधान-मंत्री इंदिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में इस कार्य को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है । तिलहन पर कीड़ों का काफी प्रकोप होता है । अतः मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की तरह कीड़ा-नाशक दवाइयों का फ्री स्प्रे कर

^English translation of the original speech delivered in Bengali.

[श्री सुरेश पचौरी]

लाही आदि कीड़ों के प्रकोप से तिलहन की फसल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है । इसकी हमें खुशी है ।

पिछले सत्र में पारित बजट में धान की फसल बढ़ाने का प्रयास करने का संकल्प प्रस्तुत किया गया था । कृषि के क्षेत्र में सहकारिता ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया हैं । सहकारी बैंक और कामर्शियल बैंक के माध्यम से किसानों से करोड़ों रुपए किसानों को ऋण के रूप में दिये गये । इस प्रकार किसानों तक जो ऋण पहुंचता है, उसका सूद कर व 14 प्रतिशत किसानों पर पड़ता हैं । मेरा इस विषय में भी आपसे विशेष अनुरोध हैं कि यह जो प्रतिशत ब्याज-दर है, इसमें कमी की जाये ।

न्यायालयों में कई लैण्ड रिफार्मस के केस लम्बित हैं । मेरा इस विषय में भी आपसे विनम्र निवेदन है कि लम्बे समय से जो लैण्ड रिफार्मस के प्रकरण निपटाये जाना हैं , उन्हें त्वरित गति से निपटाया जाये ।

जहां तक जल्दी खराब होने वाली खाद्यान्न वस्तुओं का प्रश्न है, इनके लिए भी जैसा कि पहले भी सुझाव दिया जा चुका हैं—पेरीशेबल कमोडिटीज का एक बोर्ड बनाया जाये, जो हर प्रदेश में और जहां तक कि जिला-स्तर पर यह सजेस्ट करे कि किस प्रदेश में, किस जिलें में कितना गन्ना, कितना काजू, आलू, कितना प्याज उगाना हैं ? इसके लिए मेरी आपसे यह प्रार्थना हैं कि तुरन्त कार्यवाही की जाना जरूरी है । कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे पौद विज्ञान, बागबानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि पर काम कर रहे 33 अनुसन्धान केन्द्रों में समन्वय स्थापित करने और अपने कार्यक्रम जारी करने के लिए वर्तमान सत्र में सरकार ने 790 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की हैं । दुनियां के विकासशील देशों में भारत ही एक ऐसा देश हैं जहां अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग से किसी तकनीकी केन्द्र की स्थापना की गयी हैं । यह केंद्र दिल्ली में खोला जा रहा हैं । मेरा इस सम्बन्ध में आग्रह हैं कि इसको शीघ्र खोलने की व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से संबंधित हूं और समन्वय वित्त विकास कार्यक्रम देश के सभी 5011 विकास केंद्रों में लागू है जिस का उद्देश्य गांवों की गरीबी को दूर करना है और लाभकारी रोजगार की व्यवस्था करना है और साथ ही ग्रामीण रोजगार नौजवान साथियों के लिये जो ट्रेनिंग योजना डाली गयी है जिस का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को अच्छी तकनीक से अवगत कराना है ताकि वह स्वयं का धंधा और व्यवसाय चला सकें, इस संबंध में मेरा आग्रह है कि आई एन आर ई पी और आई आर डी पी योजनायें हमारी सरकार ने बनाई हैं । उन के लिये जो एजेंसियां हैं, जिन के माध्यम से उन्हें मूर्त रूप दिया जाना चाहिए जैसे कलेक्टर, बी डी ओ और वे अधिकारी जो कि ग्रामीण स्तर से ले कर शीर्ष स्तर तक इस से संबंधित हैं उन में समन्वय स्थापित हो सके और वे मूर्त रूप इस को ईमानदारी से दे सकें इस के लिये सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था किये जाने की जरुरत है और ऐसी सख्त हिदायत दिये जाने की जरुरत है कि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की ढीलढाल नहीं की जायेगी । मान्यवर, मध्य प्रदेश को भंयकर सूखे की स्थिति का सामना करना पड रहा है । इस को राज्य सरकार अपने सोर्सेज से फेस नहीं कर सकती । केन्द्र को राज्य सरकार को इस संबंध में मुक्त हस्त से वित्तीय सहायता करना बहुत जरुरी है । आज कल मध्य प्रदेश में जैसा पानी का अकाल पड़ा हुआ है वैसा पिछले सौ सालों में भी देखने को नहीं मिला । लगभग 300 कस्बों और 15000 गांवों की हालत यह है कि अगर 10,15 दिन में पानी वहां नहीं मिला तो शायद उन कस्बों और गांवों को लोग खाली कर देंगे । मांडला और सागर जैसी जगहों से लोगों ने बाहर जा कर शरण लेना शुरु कर दिया है और यहां तक कि कई जगह बड़ी दयनीय स्थिति है और एक रुपये में एक लोटा पानी और दस रुपये में एक बाल्टी पानी मध्य प्रदेश में मिल रहा है । पग पग रोटी और डग

डग नीर के लिए प्रसिद्ध मालवा में भी यही दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है और मवेशियों की हालत यह है कि उन को नाम का चारा तो है लेकिन पीने के लिये पानी नहीं है । कालिदास के शहर उज्जैन में क्षिप्रा नदी सूख गयी है । ताल तलैया की नगरी भोपाल में जैसा कि मैं ने पिछले समय स्पेशल मेंशन में आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि भोपाल का ताल लगभग सूखने की स्थिति में है और उस का जलस्तर प्रति दिन कम होता जा रहा है । जिसके सम्बन्ध में बड़ी संजीदगी और गम्भीरता से केन्द्र से पहल किया जाना बहुत जरुरी है । सेन्टर से एक अध्ययन दल, मान्यवर, मध्य प्रदेश पिछले दिनों गया था । उस से यह मांग मध्य प्रदेश सरकार ने की थी कि मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति से और पानी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है । मेरा उस सम्बन्ध में यह आग्रह है कि ड्राउट सिचुएशन से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी वित्तीय मदद का आग्रह केन्द्रीय सरकार से किया है उतनी वित्तीय मदद केन्द्रीय सरकार से बहुत जल्दी दिलाया जाना नितान्त आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

DR. SHANTI G. PATEL (Maharashtra): Sir, while one thinks of agriculture, one is struck by its vastness and its complexities. I need hardly say that the agriculture occupies a very key position . in the context of a developing economy. It is not merely that the agricuture provides food and raw materials but also it employs a large segment of Indian population in this particular area. The rural population which amounts to 75 per cent of the total population tries to seek livelihood in this particular place in the Indian subcontinent.

While one goes through the Report, one finds that the Government or the Minister in charge has tried to paint a very rosy picture, as if everything is all right with our agriculture, rural employment and the rest of it and we need not get worried. When one goes through the report, one finds that the (record) production for the year 1983-84, as far as food is concerned, is 151 and odd million tonnes. I do not want to go into the veracity of these figures, though I have my own doubts regarding the correct ness of these figures. All tbe same. I would like to take this figure as the basis and try to see as to how we have been faring on this particularly important aspect of our Indian economy. It provides not merely stability to the economy as a whole but also it can help, if properly handled, in export earnings also. But I am very sorry to say that we have miserably failed as far as export front is concerned.

But it is claimed that we have a record production. Of course. For the next year's production there is some picture which is not as rosy, as, according to the forecast that is given, it is going to be a little less 150.5 mt. The fact that it is going to be less is something which should be a bitter warning for all of us.

Sir, it is not mv desire to go into the whole gamut of the agricultural field. But I would certainly like to go into the way in which we have reached this particular figure of production.

I must say that because there are some good monsoons we feel very elated and barmy that we have a lot of production.

[Dr. Shanti G. Patel] We have made certain advances as far as agricultural inputs are concerned, But believe this is something which should not lull us into *b.* state where we might go to sleep and ultimately we may nnd one morning mat we are witn-out enough foodgrains to feed our population. Hut an the same, I would luce to know, is this situation a matter of saustaction?

I believe that this is not a matter of sansiaction at all.

As a matter of tact, I am one of those who feel that it is a matter ot shame when we compare ourselves to the adjoining countries in the matter ot tood production. Ji we look at the hgures, we find that we are far behind even our neighbouring country, Pakistan. It is ahead of us as far as rice production is concerned. If we took at the growth rate, we find that it, has slumped down to 2.14 percent (1969—84) 9 from 2.97 per cent during 1950—69 period while the population has been rising at the rate of 2.5 per cent. Now, this is the progress which we have achieved in the years which followed the Indian Independence.

Probably, the Government spokesman or the people from the other side may try to justify that we have increased our productivity. I am informed that our productivity for wheat has gone up from 8.3 quintals in 1966 to 18 quintals per hectare in 1983-84. May I submit that this has onlv resulted in the rich becoming richer and the poo' becoming poorer. As far as the countryside is concerned, the benefits of advanced technology or scientific agricuture have mostly gon# to that section of the Indian society in tbe countryside which is already rich and which has got toe wherewithals to manage and to procure all the things which are necessary to push up the output. On the other hand, the other section, i.e. the marginal and small tanners are not able to get even the agricultural credits in tune. Firstly they don't get and whatever they are able to get, they don't get in time. As far as the inputs and other facilities are concerned, the least said the better.

I was referring to productivity. In this connection, I would like to point out that our productivity, as far as wheat is concerned, is about 1800 Kgs. per hectare. In Erope, it is 3607 and in Japan it is 3060. We are lagging also far behind in the productivity of rice which is the main diet in most parts of the country. We are having about .1380 . Kgs. per hac while Japan has 3780, South Korea 4150 and even China with whom we are trying to compete has 2825. Indonesia which is supposed to be lagging far behind! us is ahead of us as far as rice productivity is concerned. It has 2320 per hectare. As I said earlier, even Pakistan has 1600. I am referring to these figures onlv to point out as to how we have fared on this particular front.

You will be surprised that even in the case of pulses, we are lagging behind and our prodution has been stagnant for the last several years *excent* when we *hud* the Green Revolution in the 60s. We ^iav,e been st&smatwti* thereafter. Onlv the rain rod has V>een coolng to our rescue and salvaging our had crops.

As far as unless air concerned, the same sorrowhul picture is there.

As you know, pulse* are the most important constituent oi a staple normal diet ot an Indian. Pulses contain protein and tins is something which has to be provided in a country where there are so many vegetarians or where the non-vegetarians are not able to afford the non-vegetarian diet. It is very important that this very important constituent is made available to the people in abundant quantity and also at a price that they can afford. I need not go into the story of rising prices of pulses which have not come down and which are going up and up.

Even alter 37 years, our account is absolutely an account of failures and falures *falures* as far as this production is concerned. We are now expected, Sir, to have about 25 million tonnes of pulses according to the National Commission on Agriculture by the end of the century, that is the year 2000 AD. What is our performance? We a[r]e still stagnating between 10 and 12.5 million tonnes, God only knows when the population rises by the turn of the century how the people are going to be fed.

But more important in this context is that apart from the total quantum of production, the real measuring rod is the quantity that is available per *capital.* Tt was 70 grams in 1956 and it has come down *to* 39 grams in 1982. Still it is going down. That is what I would like to emphasise. Now, this is what we have fared as far as production front is concerned.

Sir. I would also like to refer to the many things about which the Government has been making claims as to how good they have been faring and trying to boost the production.

Now, m matters of oilseeds also, we have not been able to fare that well. There also we have been stagnating for years. The fact that we are required to import huge quantities of edible oils goes to show that our performance on that score also is very bad.

Coming, Sir, now to the quality seeds, there also what was expected from the Government or from the machinery which has been set up by the Government is not coming true, and we have been only showing very little progress. There have been marginal increases in oilseeds. But again when we are required to import about 1.5 million tonnes of edible oils this year, it shows only as to how miserably we have been failing.

So, Sir, take any particular item of production as far as agriculture is concerned. You will find that we have been failing and we have not been able to put out that particular performance which other countries in the region have been able to do. Their growth rates also have been quite high and I need not quote all the figures. But suffice it to say that even the whole ESCAP region has been able to have a growth rate of 3.5 ner cent while we have been lagging behind, as I said earlier.

Now, what is the reason which has led to this? Sir, I would like to say that we have not been able to mobilise the resources that we have at our disposal and administer therm in a rwooer manner.

T would like to refer to the land reforms. Sir. land reforms is a matter through which we should boosted up the production. Even unde*- the revised ceiling laws, the Government agencies have not

[Dr. Shanti G. Patel]

been able to distribute even 50 per cent of the surplus land that is available. Still some land is not taken possession of from the persons who are having the excess land. Wherever it has been taken possession of, the Government has failed to distribute it fully to the persons. As a matter of fact, hardly one *per* cent of the rural poor has got the excess land which was available after surplus.

Sir, if this particular performance has to be improved, then we have not merely to improve our farm technology but we have also to see that our agricultural credit goes to the proper persons, particularly to the marginal and small farmers. Then, Sir, the fertilizer input performance also is bad compared to any other country in the region. We just do not stand anywhere as far as the fertilizer performance is concerned. Sir, I would not like to quote the figures because of the shortage of time. But it is an obvious thing do not stand even one-tenth in the row as far as this ESCAP region is concerned. This is our dismal failure on this particular front.

Now, it is in this context that we have to develop this agriculture and unless we are able to mobilise all these resources properly, marshal them oroperly, make them available. T do not think the[r]e is going to be any good future as far as agriculture is concerned. *(Time Bell ffn&s).*

Sir, T would also like to refer to another asr>ect of the matter and that is Integrated Rural Development Programme. Of course, in the morning it was said that the Prime Minister had devoted a lot of time at the AICC session for the agriculture. But, here, in the House we are devoting perhaps the least possible time for the discussion of an important subject. One is required to say everything that one would like to say in a few minutes, when is perhaps impossible. That is why the Minister has not been able to say all in the three reports which he has submitted.

Sir, I was referring to the Integrated Rural Development Programme because this is the one programme which has been started with a fanfare and it was said that fifteen million families are going to be raised above the poverty line in the course of five years and a lot of subsidies and a lot of loan will be made available. But what are the results? Unfortunately the survey which was started by the Planning Commission or the evaluation by the Planning Commission has not still been made available to us. Whatever studies and surveys have been made by individual scholars or institutions or institutes show beyond doubt that the desired objective has not been achieved. Sir, according to Professor Nilakanth Rath, who is a leading economist and director of the Gokhale Institute of Politics and Economics at Pune, the imnact is not even 3 per cent as far as the people to be taken above the poverty line are concerned. I know that claims are being made that a lot of peoole, both in terms of percentage and quantum have been lifted above the Doverty-Vne; hut this is not taie. This itself has been challenged by a number of economists who are verv well-known in their own field, who have served on the Planning Commission, like Prof. Krishna Rai and also Mr. Sunda^am. They are leading economists and they have said that the

assumptions are wrong, which have made the Planning Commission and the other authorities say that this particular poverty-line has been crossed by a large number of people. The IRDP has failed mainly because the whole identification of beneficiaries has been wrong. There has not been proper planning regarding the supply and demand as to what that particular field or district requires, what that particular block requires. No such study has been made. Conceptually it was said at that time tbat the whole plan would be prepared as it is called integrated rural development programme. It is not "integrated". It is "individual" family upliftment programme. That is all tbat one can say. All such families are not really poor. Even well-to-do families have been given this assistance.

Even if a man has to buy a milch cattle, one has to buy a buffalo for Rs. '3,000 Rs. 500 is the bribe, Rs. 150 is the travel expenses; for Rs. 2,500 you cannot find a buffalo worth milching or which can be really of use to the person concerned. *{Time Bell rings).* One can give a number of examples. Sir, what was meant for a bribe this is again a part of the survey. Something which was for a bribe, a male partner, was given to a female partner of a bonded labourer as grant. A number of instances like this can be given. Now, if this has to be set right, then one has to go according to the original concept. There has fo be really integrated development, means various fronts have to be taken care of in a village or in the block. Before this is done, a proper study has to be made as to what is required in that particular area and then an effort, a combined effort has to be made, a determined effort has to be made, to see that these peoole who are sought to be 288 RS—8 provided with assistance are able to make real use of the assistance. Along with it, other schemes like the NREP where wages are to be paid to the workers have to be properly implemented. Unless a com-prehensive approach is thought of and implemented with the help of persons who are really committed to the good of the poor, I don't think, through the bureaucratic machinery, we can deliver the goods. So, both the concept and the administrative machinery have to be set right before we can really achieve success either in the IRDP or other programmes or for that matter even on the food front.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि मंत्रालय पर होने वाली चर्चा में मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश है । हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और आजादी मिलने के दौरान ही हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के क्या उद्देश्य हैं उसका भी निर्धारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में तय किया गया था कि हिन्दुस्तान स्वालम्बी होगा । हिन्दुस्तान गांवों का देश है । उपसभाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने मुल्क के भविष्य की जो रूप-रेखा या उसका जो खाका तैयार किया उसमें था कि हिन्दुस्तान बुनियादी रूप से गांवों का देश है और यहां 7 लाख गांव हैं और कृषि उनकी मुख्य एकानामी का आधार है । यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रीज पर आधारित है । तो हिन्दुस्तान का विकास कैसे होगा? हिन्दुस्तान के गांवों के लोग जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक हिन्दुस्तान का विकास संभव नहीं है और गांवों का विकास तभी होगा जब कि कृषि का इन्टीग्रेटेड डैवलपमेन्ट होगा । इस नजरिये को मद्देनजर रखते हुए कृषि को प्राथमिकता दी गई है । आजादी के बाद राष्ट्र

[श्री कल्पनाथ राय]

नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्लांड एकानामी के माध्यम से हिन्दुस्तान में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई । प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गई । तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग, दोनों को साथ-साथ प्राथमिकता दी गई । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश के किसानों ने 151 मिलियन टन गल्ले का उत्पादन किया । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और आदरणीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि इस साल चीनी का उत्पादन घटा है । अगर किसानों के साथ सरकार बेरुखी का रुख अपनायेगी, उनकी समस्याओं पर विचार नहीं करेगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनाज का उत्पादन आने वाले दिनों में घटेगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, 1980 में देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र की कैबिनेट ने फैसला किया कि खेतों में पैदा होने वाले सामानों और कारखानों में पैदा होने वाले सामानों के दामों में पैरेटी फिक्स की जायेगी । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 1980 और 1985 के बीच में उस पैरिटी को कायम रखा है ? आज कारखानों में बनने वाली चीजें सोने के दाम बिक रही हैं और किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों को कोई पूछने वाला नहीं हैं । इसके कारण के लगातार गांवों को छोड़ते जा रहे हैं और गांव का किसान मार्जिनल किसान, छोटा किसान जो है वह लेबर में कन्वर्ट होता जा रहा है । वे अपनी दो-दो, चार-चार बीघा जमीन जो उनके पास है उसको बेचकर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद तथा हैदराबाद के स्लम एरियाज में आबाद हो रहे हैं । देश के किसानों की समस्याओं पर बुनियादी ढंग से यदि सरकार ने विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के नेता एवं आज के प्रधानमंत्री राजीव जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया । उन्होंने चुनाव के दौरान एक घोषणा की कि हमारी सरकार एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन की स्थापना की घोषणा करती है यानी अब पहले एग्रीकल्चर की कास्टिंग होगी तब प्राइस फिक्स होगा । एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन की जो हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा कि है देश के करोड़ों किसानों की तरफ से उनकी इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं और करोड़ों किसानों की तरफ से शुभकामनाएं नये प्रधान मंत्री को हम देना चाहते हैं । उन्होंने एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन की घोषणा की लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया । इस साल किसानों के गल्ले का दाम निर्धारित किया गया, 1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आई तो गेहूं का दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, जनता सरकार के समय में जितना दाम था उससे 10 रुपये ज्यादा दाम निर्धारित किया गया, 1981–82 में फिर 10 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया, 1982–83 में 10 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया गया फिर 1983–84 में भी 10 रुपये क्विंटल गत वर्ष के मुकाबले में बढ़ाया गया । जब एग्रीलकचर प्राइस कमीशन था तो गेहूं का दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ाया गया । आदरणीय सुलतान सिंह जी जैसे हिन्दुस्तान के सैंकड़ों किसानों ने बार-बार मांग किया कि जैसे इंडस्ट्रीज के दाम को तय करने के लिए इंडस्ट्रीयल ब्यूरो इस्टेब्लिस्ड है उसी तरह से खेती की उपज का दाम निर्धारित करने के लिए पहले उस की कास्ट निर्धारित की जाए फिर प्राईसिंग किया जाए और उस मांग को देखते हुए हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन बनाया और जब इस साल गेहूं का दाम निर्धारित किया गया तो पांच रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एग्रीकल्चर कास्ट को ध्यान में रख कर के इस प्राइस को फिक्स किया है । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था तो 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ाया गया और एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन बना दिया गया तो पांच रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया । मैं अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों

का दारा कर के आया हूं, मुझे गांव में किसानों से मिलने और बात करने का मौका मिला ? मैं यह कह सकता हूं कि किसान अन्नदाता है, प्राणदाता है । किसान के बेटे ही देश की रक्षा के लिए सीमा पर प्राणों की आहुति देते हैं और किसान के बेटे ही खेतों में गल्ला उत्पादन कर के हिन्दुस्तान और देश को अनाज देते हैं । हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता और आजादी की लड़ाई में हिन्दुस्तान के किसानों ने गांवों में रहने वालों ने कुर्बानी दी थी और उन्हीं के कारण हिन्दुस्तान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है और उन्हीं के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हैं लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या हालत है, मुझे अभी गांवों में जाने का मौका मिला । पिछले साल 450 रुपए प्रति क्विंटल लोहे का दाम था। लेकिन आज लोहे का दाम 900 रुपये हो गया है । सीमेंट जो किसान खरीदता था उसका दाम डेढ़ गुना हो गया है ; कपड़े का दाम बढ़ गया है । डालडा घी जो वह अपने बेटे, बेटी की शादी पर खरीदता है उसका दाम बढ़ गया है । किसान जो भी सामान बाजार से खरीदता है कारखानों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदता है इन चीजों का दाम बढ़ गया है । खुरपा हो या खुरपी हो, गंडासा हो या कुदाल हो, फावड़ा हो, लोहे का बना हुआ कोई भी सामान हो, बैलों की जोड़ी हो या इम्पलीमेंट्स हों जितना भी सामान किसान खरीदता है सब सामान का दाम बढ़ गया है । अपना छोटा सा मकान बनाने के लिए चाहे लोहा हो, सीमेंट हो या ईंट हो कोई भी सामान हो उसका दाम इस समय डेढ़ दो गुना हो गया है । जो सामान वह पैदा करता है गेहूं, धान, गन्ना, कपास और तिलहन या कोई भी सामान हो उन चीजों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है परिणामस्वरूप उद्योगों और कारखानों में बनने वाली चीजों और खेतों में पैदा होने वाली चीजों में जो पेरिटी लाई जानी चाहिये सरकार ने जो पालिसी स्टेटमेंट तय किया है उसके तहत क्या हम पेरिटी की नीति को स्वीकार कर रहे हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की कि एग्रीकल्चर कास्ट और प्राइस कमीशन अब होगा जिसमें पहले हम एग्रीकल्चर के सामान की कास्टिंग करेंगे और फिर प्राइसिंग करेंगे तो क्या उसके अनुकूल हमने काम किया ?

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की कृषि की बुनियाद हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने रखी । हिन्दुस्तान के किसानों को ज्यादा गल्ला उत्पादन करने की दिशा में जो इन्फ्रास्ट्रचरल फैसिलिटी चाहिए उसको हमने मुहैया कराया । हमारी वैज्ञानिक कृषि नीति के कारण ही देश में गल्ले का उत्पादन तिगुना बढ़ा और 5 करोड़ टन से 15 करोड़ टन का उत्पादन पिछले 35 साल में हुआ है । यह हमारी महान उपलब्धि है । लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का विकास योरोप की नकल करके नहीं किया जा सकता है । हिन्दुस्तान गांवों का देश है। हिन्दुस्तान में 7 लाख गांव हैं और हिन्दुस्तान की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है । इसलिए जो इन्टग्रेटेड डवलपमेंट खेती का होना चाहिए वह हुआ लेकिन जिस तरह की प्राइसेज फिक्स हो रही हैं उसमें हालत क्या है ? हम तय करते हैं कि मजदूरों को 12 रुपये मजदूरी देंगे । किसानों से मजदूरों की जिंदगी जुड़ी हुई है । अगर किसान खुशी है तो उसके खेतों में काम करने वाला उसका मजदूर भी सुखी रहेगा । खेतों में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी से किसान की जिंदगी को अलग नहीं कर सकते हैं । आज क्या हो रहा है मार्जिनल फारमर्स, स्माल फारमर्स, बिग फारमर्स, ये तीन तरह के फारमर्स है । आज किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है या खेती का कर्ज चुकाना हो अथवा जो भी कर्जे सरकार से लिया हो वह देना हो या उसको मकान बनवाना हो वह यह सब काम तब करता है जबकि उसके खेत में फसल तैयार हो जाती है । लेकिन आज क्या हालत है ? सबसे ज्यादा लूट किसकी हो रही है ? मैं दस बीघा खेत जोतता हूं या आठ बीघा फसल हमारे खेत में खड़ी है उसी समय तहसील से फरमान आ जाता है कि आपके ऊपर खेती का बकाया है, यह पैसा आपको देना है । बेटी की शादी करनी है और वह फसल पर मनहसिर करती है;

[श्री कल्पनाथ राय]

या बैल खरीदना है, घर गिर गया है ईंटें खरीदनी हैं, लोहा खरीदना है या छोटा सा मकान बनाने के लिए दुनिया भर का सामान खरीदना है तो परिणाम यह होता है कि उसको मजबूर होकर अपनी फसल खलिहान में आते आते सस्ते दाम पर बेच देनी पड़ती है और आज हिन्दुस्तान में गांवों में 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई कमीशन बैठाए कि हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों में रहने वाले किसानों और किसानों से संबंधित मजदूरों पर कितना कर्ज है? पूरे कर्ज से लदे हुए हैं हिन्दुस्तान के किसान।

मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि आज क्या स्थिति हैं ? कोई खेती क्यों करे कोई खेती के पेशे को क्यों करे ? अगर कोई व्यक्ति अपने 5 बीघा खेत को 2 लाख रुपये में बेचकर उस पैसे को बैंक में जमा कर दे तो उसको 24 हजार रुपया सालाना सूद मिलेगा। अगर वह 5 व्यक्ति का परिवार है तो 24 हजार रुपए से दिल्ली में बिना काम किये वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है । लेकिन अगर कोई किसान गांव में 5 बीघा खेत जोतता है तो वह सवेरे 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता है लेकिन नून तेल और लकड़ी के चक्कर में ही उसकी जिंदगी बीत जाती है और उसके ऊपर कर्ज लगा रहता है । फिर खेती में कोई व्यक्ति दिलचस्पी क्यों लेगा यह एक बुनियादी प्रश्न है । आज की कीमत पर अगर कोई व्यक्ति अपनी 5 बीघा या 10 बीघा जमीन को बेचकर उस रुपये को बैंक में जमा करदे तो उसका मूल रुपया बैंक में पड़ा रहेगा और उसके सूद से उसे जो रुपया मिलेगा उससे वह अपने 5–10 व्यक्ति के परिवार का भरण पोषण बिना काम किये कर सकता है । लेकिन जो व्यक्ति दिन रात देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम करता है दिन रात खेतों में परिश्रम करता है और अपनी सरकार के आवाहन पर अपने मुल्क के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करता है उस व्यक्ति की हालत आज ऐसी हो रही है कि खेती का काम छोड़कर शहर की तरफ भागता है और दिल्ली या बड़े बड़े जो नगर हैं या छोटे भी नगरों में जो स्लम्स बढ़ रहे हैं उनके बढ़ने का बुनियादी कारण यही है कि 7 लाख गांवों के लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं ।

3 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा निवेदन यह करना है कि आज देश के सामने बेरोजगारों का संकट है । लाखों-करोड़ों नौजवान बी० ए० एम० ए० पास करके रोजी-रोटी की तलाश में प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर कारखानों में काम करने के लिए दिन-रात दौड़-धूप कर रहे हैं । खेती करने वाले किसान का लड़का दो सौ रुपये महीने की नौकरी करना चाहता है। वह सौ रुपये महीने पर काम करना चाहता है । वह खेत में काम करना नहीं चाहता । कारण यह है कि खेती लाभप्रद नहीं है । खेती से रोजी-रोटी चलाना मुश्किल है । इसलिए हिन्दुस्तान की खेती को आज अगर प्रोफिट-ओरिएंटेड बनाया जाए तो हिन्दुस्तान के नौजवान जो कि बेरोजगार होकर इधर-उधर घूम रहे हैं वे खेती के कामों में दिलचस्पी लेंगे, खेती के कामों में उनकी रूचि बढ़ेगी । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वैज्ञानिक कृषि नीति के कारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलने के कारण, भाखड़ा नंगल से लेकर नागार्जुन सागर तक जिन पर कि वैज्ञानिक कृषि नीति निर्भर करती है और उसी का परिणाम है कि हमारा कृषि उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 15 करोड़ टन हुआ है । इसी वैज्ञानिक नीति के कारण ही खेती में काम आने वाले उपकरण और ट्रैक्टर्ज के कारखानों का निर्माण हुआ है, पैस्टीसाइड और इनसैक्टीसाइड्ज के कारखानों का निर्माण हुआ है । हमारे देश के अन्दर भाखड़ा नंगल और नागार्जुन सागर जैसे बांध बने हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर हैवी इलेक्ट्रीकल्ज और पावर सैक्टर को मजबूत किया गया है और उसके कारण हमारे देश के कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है । इस वर्तमान हालत के होते हुए भी, उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का अन्नदाता किसान

इस समय इसलिए संकट से गुजर रहा है कि खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम उसको ठीक से नहीं मिल रहे हैं । इसके विपरीत कारखानों में तैयार होने वाली चीजों के दाम दिन-दूने रात-चौगुने बढ़ते जा रहे हैं । परिणामस्वरूप इस देश का किसान कारखानों की चीजों बढ़ते जहुए दामों के कारण आज संकट के दौर से गुजर रहा है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मुझे कहनी है, जो मजदूर किसानों के खेतों में काम करते हैं उनके लिए सरकार ने एक्ट पास किया है कि उन्हें 12/-रुपये मिनीमम मजदूरी दी जायेगी, लेकिन वह मजदूरी उसे मिल नहीं पाती । मजदूर भी यह बात जानता है कि हमारा मालिक हमको पांच रुपया भी नहीं दे सकता । वह अपनी मजदूरी भी पूरी प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं कि उसका मालिक उसे पांच रुपया भी दे सके । इसलिए अगर मजदूरों को मिनीमम वेज 12/- रुपया देना है और आप चाहते हैं हिन्दुस्तान के करोड़ों खेत मजदूरों को 12/- रुपये मजदूरी मिले तो खेत और खेती में काम करने वाले किसानों की हालत पर पुनर्विचार करना पड़ेगा । खेती को भी प्रोफिट ओरिएंटड बिजनेस बनाना होगा ताकि हिन्दुस्तान के करोड़ों नौजवान जो कि 200/- रुपये की नौकरी के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं, खेती की तरफ आकर्षित हों और जिससे कि वे खेतों में ही काम कर सकें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री चिमनभाई मेहता) : आप संक्षिप्त करें ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं एक बात कह करके खत्म करुंगा । आज खेत में पैदा होने वाली चीजों की क्या हालत है । बम्बई में 6/- रुपये किलो आलू बिक रहा है और फर्रुखाबाद में एक रुपये का छः किलो आलू कोई खरीद नहीं रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में किसान अपने खेतों से आलू खोदने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आलू खोदने में और खोद करके उसे ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा लगेगा वह पैसा भी वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं । लेकिन अगर आप फाइस स्टार होटल में एक प्लेट चिप्स आलू की मांगे तो 50/- रुपये का दाम देना पड़ेगा । इसलिए सरकार को अपनी नीति ठीक से तय करनी होगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री चिमनभाई मेहता) : कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री कल्पनाथ राय : इसलिए आपको खेतों में पदा होने वाली चीजों का उचित मूल्य, रेम्युनरेटिव प्राइस देना होगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहना चाहूंगा, आप भी जानते हैं कि इस समय 12 सौ करोड़ रुपये का एडीबल आयल हम विदेश से मंगा रहे हैं । अगर देश की सरकार ऐलान करे कि हम एडीबल आयल या तिलहन के लिए रेमूनरेटिव प्राइस देंगे तो हिन्तुस्तान के किसान इतना तिलहन पदा कर देंगे कि एडीबल आयल पर जो हम 1200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उस का संकट दूर हो जायेगा और एडीबल आयल में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर के हम देश को शक्तिशाली बना पायेंगे । हमारे देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य फूड, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लायमेंट रखा था। फूड, प्रोडक्टिविटी और एम्पलायमेंट के सिद्धान्त को अपने देश में लागू करना है तो खेती को लाभप्रद बनाना होगा । तभी हिन्दुस्तान में सातवीं योजना फूड, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लायमेंट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी । धन्यवाद ।

(**उपसभापति महोदया** पीठासीन हुई)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, जिस प्रकार कृषि पर बहस के दौरान समय के आंवटन की कमी है, उसी प्रकार देश की कृषि की स्थिति है । कृषि मंत्रालय में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है । मैं देख रहा था, कल्पनाथराय जी ने अपना भाषण शुरू किया, उनके शुरू करते ही घंटी बज गयी, कांग्रेस बैंच पर होने के कारण वे इतना बोल गये, लेकिन

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

हम लोग तो शायद कृषि के विभागों के नाम ही गिना पायें तो शायद घंटा बज जायेगी । मुझे पता नहीं राज्य सभा में किस प्रकार विषयों पर चर्चा के लिए समय आबंटित किया जाता है । कार्य व्यवस्था देखने वाली समिति को इसका पता नहीं रहता कि इस सभा में प्रबुद्ध विचार के लिए पर्याप्त समय मिले ।

अधिक उपज के सवाल को छोड़कर, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विषय में चर्चा करना चाहूंगा जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और जो खर्च करने में भी असमर्थ है । मैं उसका हिसाब देख रहा था, दिसम्बर तक 28 प्रतिशत खर्च आबंटन का किया था । बाद में मार्च तक का उस ने कितना खर्चा किया या निगल गया, मैं नहीं जानता । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जो हिन्दुस्तान के सामने तीन-चार प्रश्न हैं उनका निराकरण नहीं खोजा है । पेट्रोल के बाद अगर देश को किसी चीज का अधिकतम आयात करना पड़ता है तो वह खाद्य तेल है । पहले खाद्य तेल 4100 रुपये टन था, फिर 6 हजार रुपये टन हुआ, फिर 8400 रुपये टन हो गया । वे लोग समझते हैं कि भारत उन पर निर्भर है तो दाम बढ़ाते जाओ । खाद्य तेल में हम 1950 में जहां थे वहीं हैं । कृषि अनुसंधान परिषद् क्या करती है ।

जब मैं दूध की बात उठाता हूं चाहे बाहर या सदन में तो हमारे कृषि मंत्री कहते हैं दूध का उत्पादन बढ़ गया है जबकि 75 करोड़ रुपये का मुफ्त दूध का चूर्ण हमको मिलता है और वह हम ढाई-तीन शहरों को पिलाते हैं । डेरी डेवलपमेंट हुआ है तो यही हुआ है कि आप किसानों को पैसा देकर दूध संग्रह करके निचोड़ लेते हैं । गुजरात में बहुत विकास हुआ है । लेकिन गुजरात में लीला क्या है ? आज गुजरात में एक-दो घर के बाद यक्ष्मा का पेशेंट है । आप दूध ले लेंगे तो होगा क्या ? गुजरात सम्पन्न राज्य होने के बावजूद वहां बच्चों की मृत्यु दर अधिक हो गयी है । डेरी डेवलपमेंट क्या कर रहा है ? उस पर रुपया लग रहा है । उन का क्या हो रहा है । इस वक्त सब से बड़ा बुनियादी सवाल है कि पशु का विकास कैसे हो । पशु के विकास के लिये कितनी ही योजनायें देश में चल रही हैं और वे सब फ्लाप हो रही हैं । एक योजना को बेकार कर के अभी बंगाल सरकार को दे दिया गया । उस के लिये 2200 गाय दी गयी थीं और अब उस में से केवल 200 बची हैं । 300 अधिकारी उस योजना के लिये थे, आज भी वे 300 ही हैं । कई बार कहा गया कि लाखों रुपया उस पर खर्च हो रहा है दूध की पैदावार बढ़ाने के लिये, तो इस में से केवल इतनी ही सड़ी गली गाय क्यों बच पायीं । जवाब आया कि सब ठीक ठाक है और अब इस को बंगाल सरकार को दे देते हैं । तो सारी योजनाओं में यही हो रहा है । वे कहते हैं कि जर्सी गायें ला कर विदेशों से अपनी अच्छी नस्ल बनायेंगे, लेकिन हम शहरों में रोज देखते हैं कि अच्छी नस्ल की गायें रोज कटती हैं । कलकत्ता, बंबई और दूसरी जगहों में स्लाटर हाउसेज में कटती हैं...

उपसभापति : बंबई में गायें नहीं कटतीं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हर जगह कटती हैं । अच्छी गायों के लिये भी दस रुपये में सर्टिफिकेट मिल जाता है । (**व्यवधान**) और आप के मोहल्लों में भी कटती होंगी । आप वह देखने नहीं जाती होंगी । आज अच्छी गायों की नस्ल खत्म होती जा रही है और सब से बड़ा इस का सबूत यह है कि बहुत बड़ी संख्या में आप मांस का निर्यात करते हैं । मांस का निर्यात देखने से ऐसा लगता है कि एक-एक गाय में कई टन मांस होता होगा । रोज नये स्लाटर हाउसेज खुलते जा रहे हैं । तो इस तरह से गाय या भैंसों की संख्या नहीं बढ़ रही है । आज चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं । जैसे-जैसे सिंचाई बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे चारागाह के लिये जगह

समाप्त हो रही है । लोग गंगा के किनारे सौ, पचास गायें पाल लिया करते थे लेकिन अब एक गाय रखना भी मुश्किल हो रहा है । अच्छी नस्ल का प्रचार आप कर नहीं पा रहे हैं । तो यह बातें आखिर कब तक चलेंगी । दूध का चूर्ण आप लोगों को कब तक दे पायेंगे । यह तो 90 तक ही चलने वाला है । 60 हजार टन चूर्ण आप मंगा रहे हैं तो एक अरब रुपया तो आप चूर्ण मंगाने पर ही खर्च करते हैं । आप मछली, मांस और अंडे की बात करते हैं । मछली तो दस ग्राम से भी कम पड़ती है । मछली की एक आंख की वजन से भी कम । तो देश में एक भयावह स्थिति है चाहे वह तेल की बात हो या दूध की बात हो या दाल की बात हो । दाल के लिये आज तक कोई अच्छा बीज उत्पन्न नहीं हो सका । हम उन से बोज ले जाते हैं और बोते हैं तो 8,9 मन पैदा होता है । क्या इस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता ? तो खाद्य तेल, दूध और दाल की समस्या प्रमुख है और जिन पर भारतीय अनुसंधान परिषद ने पूरा ध्यान नहीं दिया है । वह तो एक गुट के हाथ में है और वह कुछ नहीं कर पा रही है । आज वैज्ञानिक भागे क्यों जा रहे हैं । वे कहते हैं कि हम को दूसरी जगहों में अच्छा वेतन मिल रहा है । उस का एक पुराना इतिहास है । भारतीय वैज्ञानिक परिषद में जब अधिकारी घिरता है तो या तो वह मौत से खेलता है या फिर अवकाश पर भाग जाता है या फिर नौकरी छोड़ता है । थे ने राव बीरेन्द्र सिंह जी से एक वैज्ञानिक के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं संतोषजनक रेकार्ड दिखलाउंगा जो कार्यवाही की गयी है उस बारे में । थे ने कहा कि आप नहीं दिखला सकेंगे और वे नहीं दिखा सके । बूटा सिंह जी भी आये और वह भी नहीं दिखा सके । अगर सब ठीक है तो देश की पैदावार ठीक क्यों नहीं हो रही है । गेहूं की पैदावार इस लिये बढ़ी है कि मैक्सिको का बीज हम को मिला । हमारे देश की पैदावार बढ़ाने के लिये हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया । किसी चीज की पैदावार बढ़ी है तो बताया जाता है कि इतने टन पैदावार बढ़ी, यह बता दिया जायेगा कि दस मिलियन टन ज्यादा पैदावार हुई, लेकिन यह कैसे हुई यह नहीं बताया जाता फिर कहा जाता है कि पैदावार ढाई प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन पापुलेशन के रिकर्ड से जो पैदावार हो रही है वह क्या है ? यह एक दृश्य है लोगों के सामने जो मैंने संपूर्ण देश के बारे में आप से कहा ।

अभी कल्पनाथ राय जी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का हल नहीं किया गया है। जो उनके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, कृषि विज्ञान के केन्द्र खोले गए, मैं कोई किताब पढ़कर नहीं कह रहा हूं। मैं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर जाकर देखता हूं कि उनकी क्या हालत है । हमने 50 किसानों को, भूमिहीन किसानों को कुछ बीज खाद दे दी और कहा कि वहां लैंड टु लेब का इंतजाम किया है। लेबोलेट्री का ऐक्सपेरिमेंट तो जमीन पर होगा। जहां जमीन ही नहीं है, वहां आप क्या ऐक्सपेरिमेंट करेंगे । मैंने के० वी० सेन्टर मुंगेर में देखा । वहां लोग कहते हैं कि पूरा पैसा ही नहीं दिया गया । पैसा युनिवर्सिटी खा जाती है । निजी संस्थानों को जो आप देते हैं, वे कुछ अच्छा काम कर रहे है । लेकिन किसी भी चीज की अगर हम लेते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तो उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम में पशु देने का प्रबन्ध किया गया, जब लोग पशु को लूटकर खा गए तो आपने कहा कि उसको बन्द करो। हर क्लेक्टर को आपने एक करोड़ से दो करोड़ रुपया खर्च करने का अवसर दिया जिसमें हर जिले के हर आफिसर को करप्ट बना दिया है । जब भी आप पैसा दें तो उसकी जांच-पड़ताल करें, अगर जांच-पड़ताल नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा ।

कृषि विभाग के एक दर्जन और विभाग हैं जिनका कोई कोआर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है । तीन चार विभागों से मेरा वास्ता पड़ा। वे कहते है कि हमारा काम प्लांट प्रोटेक्शन का है, हमारा काम सिचाई का नहीं है। दूसरा कहता है कि हमारा काम सिचाई का है।

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

लेकिन उनमें कोई काम समन्वित ढंग से नहीं होता। एक किसान कितने दरवाजे तोड़ सकता है। इसका निदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग बना। उसको फिर अग्रिकल्चर में जोड़ दिया। काम अच्छा होने के लिए विभाग बनाया तो फिर क्यों जोड़ दिया? अब फिर उसका अलग मंत्रालय बनाया तो इस तरह से कैसे काम होगा?

महोदया, अमरीका एक धनी देश है, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश है। लेकिन उसका मूल आधार क्या है? मूल आधार उसका उद्योग नहीं है, मूल आधार उसका मैकेनिकल डैवलपमेंट नहीं है। मूल आधार कृषि का विकास है। उसने उसको इतनी पूंजी दी है, इतना आगे बढ़ाया है, इतना सम्मान दिया है कि भारत को, इस की भी उसके सामने हाथ पसारना पड़ता है। लेकिन आज जो कृषि हम दे सकते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं, वह हम समझ नहीं सके हैं। जिस चीनी को हम इतना पैदा कर सकते हैं कि दुनिया के दो चार देशों को खिला सकें, वह भी हमारे यहां नहीं है। एक तरफ बम्पर क्राप कहते हैं, दूसरी तरफ आयात करते हैं। कहते हैं कि हम सैफ्टी के लिए कर रहे हैं कहीं पर भी हमें अपनी कृषि पर भरोसा नहीं है। सिंचाई के लिए दुनिया भर हमारी शिकायत करती है, जब बम्पर क्राप हो जाती है तो कृषि विभाग अपनी पीठ थपथपाता है और जब मानसून बिगड़ जाता है, देश में हाहाकार मच जाता है तब पता लगता है कि हमारी 70 से 78 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर करती है। मैंने देखा साउथ कोरिया में जितनी बारिस होती है उसकी बूंद-बूंद उठाकर किसानों के खेतों में पहुंचाई जाती है। हमारे यहां गंगा बहती है, बंगला देश उसके पानी के लिए लड़ता है, लेकिन हम उसके पानी का कुछ नहीं लाभ उठा सके। हमारे बिहार में दो तिहाई जमीन में अंडर-ग्राउंड वाटर है लेकिन बिहार में सिंचाई की प्रापर व्यवस्था नहीं है। 4 सौ लाख से अधिक एकड़ जमीन होते हुए भी बिहार में किसान को काम नहीं मिलता है। वह आज या तो कलकत्ता में रिक्शा खींचता या पंजाब हरियाणा जाकर मजदूरी करता है खेतों में या रिक्शा चलाने के लिए अन्य शहरों में जाता है। हमारे मित्र ने कहा कि सरकार को पता नहीं, जितनी म्यूनिसिपैलिटियां हैं उनके पानी का निकास करके खेतों में जाने दें तो पैदा वार बढ़ सकती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नगरपालिका के क्षेत्र में भरपूर खेती हो सकती है, लेकिन अगर कोई सुने ही नहीं तो क्या किया जाए?

मैं इस बात को समझने के लिये एग्रीकल्चर एजुकेशन पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एग्रीकल्चर एजुकेशन में जाने वाले छात्रों को देखिये वे न गांव के होते है न गांव की समस्या समझते है और न लौट कर गांव जाते हैं सभी शहर के होते हैं, 98–99 प्रतिशत शहर के होते हैं। वे गांव में नहीं जाते हैं। किसानों की कोई प्रोब्लन विलेज की कोई प्रोब्लम उनके सामने नहीं रखी जाती। शहरों के छात्र तो किसानों के बीच आते ही नहीं है बल्कि जो गांव के छात्र इंजीनियर बन जाते हैं वे भी गांव के किसानों के बीच नहीं आते। किसान का एक लड़का इंजीनियर बन गया। मैंने उससे पूछा क्यों भई अब तो तुम इंजीनियर बन गये अब तो तुम किसानों की सेवा करोगे, खेती में मदद करोगे। उसने कहा, चाचा जी जो अफसर बन जाते हैं वह हैं वह किसानों के बीच नहीं पहुंचते हैं। जो हमारे अनुसंधान हैं, कृषि मंत्रालय के अफसर हैं वे भी किसानों के बीच नहीं पहुंचते। अगर वे किसानों के बीच नहीं जायेंगे तो किसानों की समस्या कैसे समझेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो है इसके बड़ अफसर से लेकर, डायरेक्टर जनरल से लेकर नीचे के अफसर तक को यह निश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी कम से कम एक महीने से लेकर 9 महीने तक चाहे जिस स्तर का हो, उसको किसानों के बीच में रहना होगा और अपने अनुसंधान के आधार पर किसानों की समस्या किसी भी कीमत पर हल करनी होगी। उनकी समझदारी बढ़ानी होगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं होती है। अभी तक इस पर चर्चा हो चल रही है।

उपसभापति : आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं विशेष-विशेष बात की चर्चा कर रहा हूं, विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी दिक्कत को समझता हूं।

उपसभापति : आपका टाइम बहुत पहले खत्म हो गया था। आपके आठ मिनट थे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं समाप्त ही करना चाहता हूं। आपकी कठिनाई समझ रहा हूं लेकिन कुछ मोटी-मोटी मुख्य-मुख्य बातें कहना चाहता हूं। हम लोग उसमें पले हैं, उसमें रोज बैठते हैं। अगर हम उनके दर्द को यहां नहीं रख सकते तो फिर कहां रखेंगे। मैं तो विद्वानों की बात कहता हूं। जो इस क्षेत्र में विद्वान हैं उनको वहां किसानों के बीच में भेजना चाहिये। दूसरे यह कहना चाहता हूं कि कृषि मनेजमेंट की पढ़ाई के साथ व्यावहारिक पढ़ाई भी होनी चाहिये।

दूसरे क्राप की प्लानिंग होनी चाहिये। कहां क्या पैदा किया जाए, कब पैदा किया जाए इसकी उनको जानकारी देनी चाहिये। सारी फसलें सब जगह बोई नहीं जा सकती। सारे फसलें हर समय उगाई नहीं जा सकती। कम से कम वैज्ञानिकों को, एक्सपर्टस को कैटेगराइज करना चाहिये कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी फसल किस-समय उगाई जा सकती है। इसी तरह से प्लांट प्रोटेक्शन की बात है। आज ईख में बीमारी लगी हुई है इसको कौन देख रहा है। कोई वैज्ञानिक, एक्सपर्ट वहां नहीं जाता यह बताने के लिये कि इसमें क्या बीमारी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कारण यह होता है कि उनकी सारी फसल बेकार हो जाती है। तीसरे आलू ज्यादा पैदा हो गया है तो उसके सही दाम उनको नहीं मिल रहे हैं। इस भाव को कैसे किसानों को दिया जाए इस चीज को आपको देखना होगा। भारतीय कृषि मंत्रालय में इन बातों का जिक्र नहीं होता। (*समय की घंटी*) मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। हर फसल के लिय किसान को जुताई की, सिचाई की आवश्यकता होती है। इसलिये किसानों के लिये जो जोतने का यंत्र हो वह सही ढंग का हो। पहले ट्रैक्टर किसानों को किराये पर मिलता था लेकिन अब वह किराये पर नहीं मिलता। ट्रेक्टर मध्यम और बड़े किसान ही खरीद सकते हैं छोटे किसानों के लिये ट्रेक्टर नहीं है। हमारे देश में 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं और 15 प्रतिशत मध्यम और बड़े किसान हैं। 85 प्रतिशत किसान हल ही चलाते हैं। पावर टिल्लर की बात चलती है। अगर इसको ठीक किया जाए तो जुताई, प्रोसिंग दलाई सिचाई ठीक हो सकती है। पावर टिल्लर का बंगलौर में ही एक कारखाना है। वह सप्लाई करता है। मैं अमेरिका और जापान में कई जगह गया हूं। इन चीजों को वहां देखा। मैंने बार-बार चिट्ठी लिखी, हुक्मदेव जी ने भी चिट्ठी लिखी लेकिन कृषि विभाग की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं आया। वह कह सकते हैं कि उद्योग विभाग इसको देखता है लेकिन उद्योग विभाग से भी कोई रिसपोंस नहीं आता है। मैंने उनको कहा कि पावर टिल्लर ठीक करो लेकिन कोई नहीं सुनता। हम लोग किसान के पावर टिल्लर ठीक नहीं कर सकते, आप लोग उनकी मदद नहीं कर सकते, उद्योग विभाग कुछ मदद नहीं कर सकता, कृषि विभाग कुछ मदद नहीं कर सकता, हम मदद नहीं ले सकते तो साधारण किसान क्या ले सकता है। आपका जो यांत्रिक मामलों का विभाग है, वह क्या करता है? आप करोड़ों रुपया इस विभाग पर खर्च करते हैं। अगर इस विभाग का कोई उपयोग नहीं होता है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। हम इस संबंध में लिख कर थक जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह

[श्री जगदम्बा प्रसाद यादव]

चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा कीजिये कि जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके। मंत्री जी यहां पर कहते हैं कि अब हमारा ध्यान इस तरफ गया है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हू कि तीन चार वर्ष में इस विभाग का लेखा-जोखा लिया जा सकता है। आप चार करोड़ रुपये खर्च करके एक चूजा डेवलपमेन्ट के लिए मंगाते हैं। इसी प्रकार की दूसरी योजनाएं भी हैं जिनका पूरा-पूरा लाभ किसनों को नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह नम्र निवेदन है कि कुछ ऐसा कीजिये कुछ इस प्रकार की बातें हमारे सामने रखिये कि जिससे हमें भी लगे कि कुछ हो रहा है और किसानों को भी लाभ पहुंच सकें।

SHRI KAMALENDRU BHATTACHARJEE (Assam): Respected Madam Deputy Chairman, we all know that agriculture is the backbone of India's economy. One economist has very aptly remarked: "If we are late in doing one thing in agriculture in India, we are late in doing all things in India." This particular statement very befitting-ly reveals the real state of Indian economy. It brings home to everyone what the importance of agriculture in India is. Our dynamic Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, has said: 'India's economy is very largely that of a farmer. We should be doing many things for the farmers in the coming years. We should see that there is a sharp increase in our agricultural production."

One thing Respected Madam Deputy Chairman nowadays we all *talk* in terms of high technologv, we all talk in terms of modernisation. These have become the in-thing in the present-day society. One thine we have to bear in mind. When we think in terms of high technology, when we speak in terms of modernisation, we must bear in mind the millions and millions of fanners who are toiling hard in the field in season and out of season, day in and day out, who are doing all their best and then might, to build a strong and united India, who in the language of Edwin Malcolm, are the men we must always keep in mind. This high technology is meaningless to an average farmer in India. This high technology has no relevance in Indian economy. If modernisation does not percolate down to the poorest of the poor farmer in India, this modenisation is simply out of context in India. But it is a highly welcome sign that there is a tremendous increase in our country of late in use of fertilizers, in the use of pesticides and insecticides and in the use of all the varieties of high-yielding seeds. Even an average farmer is used to the names of pesticides like BTC, DDT, Melothyne, Methylene, etc. It shows that high technology has gone down to the grass root level and it has reached the door-steps of every Indian farmer. It is indeed a heartening sign that the same Indian farmer who some years back was apathetic towards the idea of modernisation knows today the names of all new varieties of high-yielding seeds like Shukandar, OUT 101. Pratan Dhova. Safhi, Rudra Shankar, CR 1010, BK 79, MDU 2 and many other things. So far as the high-vielding varieties of rice are concerned, the same person knows the names of the high-vielding. varieties like HD-2281, Suiata. etc. What T mean to say is that modernisation and high technologv have reached millions and millions of our farmers in the country and they have gone to the grassroot and that is why we have seen

the two Green Revolutions, one in the late '60s and another in 1983-84. I would like to compliment the farmers of India, the scientists who

are connected with this and the Government which was pursuing a very progressive and fruit-bearing strategy to achieve this. For a country like India, which was not self-sufficient in food, this indeed is no mean achievement. At the moment, so far as food production is concerned, we have achieved self-sufficiency. I would also like to compliment the Department of Agricultural Research and Education as it has contributed to a great extent towards this achievement. The efforts to build up a sound food security system in the country have received a fresh impetus. The bright agricultural secnario since 1983-84 marks a distinct departure from last year's dismal performance. The achievement on the farm front in 1984 not only reaffirms the nation's confidence in becoming self-sufficient in foodgrains, but also, more importantly, underscored its potential to emerge as an exporter of foodgrains. For the first time, the original Plan targets were reached a year ahead. These developments have been described as ushering in of the second Green Revolution and unlike the previous one, it is completely Indian in all respects and its strategy and its technology are cent per cent Indian and that is why we say that it is entirely Indian in making and in character. Interestingly, it is more comprehensive in terms of crops and in terms of the area covered. Now, it is to be noted that such an achievement is the result of long-term planning and the imaginative fruitbearing strategies. Our fanners and our scientists and all the persons connected with the agricultural development in the country are fully geared up to the needs of India which would be needing 233 million tonnes of foodgrains by the end of this century and I am confident that our Government, with its very dynamic policy under the leadership of Rajivji, will be able to fulfil this target of foodgrains production which we would be needing towards the end of this century. We have seen it for ourselves in Assam. Way back in 1971, in Assam, only 21,000 hectares were under the production of wheat. But, as a result of the imaginative and innovative planning, the area covered has shot up to more than 2 lakhs of hectares and this is really a very great achievement. How has this been achieved? This has been achieved through a systematic and long-term planning. The farmers were asked to use some sort of early-maturing variety of crops as a result of which they could sow and reap wheat in early winter and the Government was paying a subsidy of a hundred rupees per quintal to the farmers and Assam advanced forward in wheat production. Moreover, a pilot project has been launched in 51 selected blocks in Assam, Orissa, Bihar, West Bengal, eastern parts of MP and U.P. as a forerunner of the special rice production programme to be taken up in the States during the next Plan. So far as foodgrains production is concerned, there can be no room for complacency. The Government is well aware of this and, in reply to an Unstarred Question in the Rajya Sabha on the 27th July 1984, the then Minister of Agriculture had clearly detailed the action plan for increasing the production of foodgrains in India. The important measures taken to Increase the production of foodgrains in different States are as follows: (i) Expansion of area

Latin Kamalendu, Bhattachari-jee]

under irrigation; (ii) Larger and efficient use of fertilisers; (iii) in-creased distribution of quality seeds; (iv) Adoption of adequate" plant protection measures; (v) Greater emphasis on soil and water conser-vation and improved dry land farming practices; (vi) Expansion of area under high yielding varieties; (vii) Transfer of technology through reorganised extension system of Training and Visit; (viii) Training of farmers and Extension workers; (ix) Intensification of research'; and (x) Adoption of appropriate pricing policies.

Respected Deputy Chairman, we have got to agree that agricultural price policy that has given remu-nerative price to the farmes, man-agement of natural calamities and effective implementation of crop in-surance scheme, all these form very important components of the Gov-ernment strategy for promoting agricultural production. But the Government has to give a serious thought to it. People are very hopeful about these projects, and if these are not properly implemented, if these remain really projects on paper, then the people will be frustrated. At the moment they are having high expectations. I would, therefore, Respected Madam, like to draw the attention of the Agriculture and Rural Development Ministry, to give their sharp and pointed attention to this particular aspect that these schemes do not merely remain on paper but they are put into effect.

Now, agriculture continues to re-ceive special attention even in the new 20-Point Programme. The Department of Agriculture is con-cerned with three items which are included in the 20-Poi»t Pro-gramme: Development of dry land farming, production of pulses and oilseeds and afforestation. Now, in my State there are three crucial hurdles. If we cannot overcome them, there cannot be increased agricultural production. What I mean by my State,—is Assam. There are three important problems. One is flood; second is irrigation and the third problem is electricity. It sounds a bit paradoxical when I say that Assam, though it is full of water resources, has three problems as I have mentioned. If we cannot tame Barak and Brahmaputra and tap these water resources and harness them to the people's service, these cannot be turned into blessings. At the moment, the Barak Gandak project, which is before the Government of India, has been cleared at the technical level, and it only now requires final clearance. And if administrative and financial clearance is given, green signal is given, this work can be taken up. Respected Madam, through you I would like to request the Minister j of Irrigation and Power to give liberal financial assistance to this project, or the Finance Minister, so that he can give liberal financial assistance, so that the work can be I taken up by NECR. There is also the pressing need for setting up an Agricultural University in Assam. The most backward district, that is, [1] the district of Kachar, should be the '- venue for the Agricultural Univer-sity.

Now, at the moment only 27 lakh hectares of land are under irrigation in Assam and the percentage of coverage would be just 16. Compared to all-India standards, this percentage is not very good. I would, therefore, like to request the Government through you, Madam, to give liberal financial assistance

tor this so that more and more areas could be covered by bringing more and more land under irrigation scheme. The Government of Assam has already seen that the micro irrigation projects are not very successful. The results are tar from being satisfactory. So, more and more funds should be released for making successful the micro irrigation projects. Before, I conclude 1 would like to compliment the farmers of India, the scientists and our Prime Minister for his insistence and assurance to do his best for the increased agricultural production in India and also the Agriculture Minister for bringing in the second Green Revolution in India. If we go on maintaining this tempo, I am really confident that we will be able to meet the needs of our people and that we will be able to build a strong and prosperous India. With these words, I conclude.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I begin my speech on this vast and important subject of agriculture which is all compassing with the famous words of saint-sage of India, Thiruvalluvar, which mean that only those who earn their livelihood and lead their lives by pursuing agriculture are the people who really lead a life. All the others are those who just follow them. That is, they are only second grade. This emphasises the importance of agriculture. It is not as if we do not know that 80 per cent of our country lives in villages. That is why our late lamented father of the Nation who is now more forgotten than remembered., Mahatma Gandhi, gave his own importance to the agrarian economy.

While discussing this Ministry. T do not want to go into the controversy whether "India should be an agriculture-based economy or industry-based economy. Recently, there was a mention by our friend here from the Lok Dal about our former Prime Minister, Shri Charan Singh J Ts book wherein he has said that importance should be given to agriculture. There are others who are of the view that importance should be given to industry. While 1 welcome a mixed economy for our country, it should not be forgotten that ours is largely an agrarain economy. Madam, nearly 329 million hectares of land are there in India out of which only 140 million hectares are under cultivation which is about 53 per cent of the total land available. It is really a very poor figure as compared to world standards. As has been said and is well known, India's economy particularly for a farmer is a gamble in the monsoon. Therefore, proper emphasis should be there on irrigation and wherever possible, irrigation facilities should be made more and more available as the dry-farming techniques are not catching up as they should. In this connection, I would suggest an early implementation of the garland canal scheme which was there for every State. To add to this, even as early as 1920, Sir C. P. Ramaswamy Iyer had originated the idea of linking the Ganga with the Cauvery which was indeed a grandiose scheme. Al that time when the Britishers were there, it was expected to cost oni} 2000 crores. To connect Gang* withi Cauvery would have resulted not only in bringing thousands o acres of land under cultivation, buy would have also provided employ ment opportunities. Even our foi mer Irrigation Minister, Mr. K. I Rao. when he was there, pursue the scheme very vigorously. Bi somehow it h?s been <riven the S(by. Tt has got two difficulties. Or

[Shri R, Rama Krishnan]

by. it has got two difficulties. One is the finance. Today, the cost will be running into something like 50,000 crores of rupees. Secondly, pumping of the water across the Vindhayas will pose a technical problem which can definitely be surmounted. I urge that die Ministry of Agriculture should follow this up with the Ministry of Irrigation and soon have a scheme which will provide not only the much-needed fillip to our Indian agriculture, but also employment to thousands of people. So many things can be said, Madam, because this is a vast Ministry. I congratulate the Prime Minister for making a proper composition of this Ministry, and again regrouping the Departments. Formerly, we had only the Ministry of Food and Agriculture. But because it had become so big, this was separated. Now, the Prime Minister has logically taken the Agriculture and Rural Development Ministry as one with three Departments—the Department of Agriculture and Rural Development; the Department of Agricultural Research and Education; and the Department of Rural Development. Now three Departments are there. This new combination is welcome, and I hope it is going to produce the results.

Now, coming to one important subject under agriculture, namely fertilizer, Madam, India is the fourth largest consumer of fertilizers in the world after the United States of America, the USSR and China. And today we are consuming nearly 84 lakh tonnes of fertilizers out of which 60 to 65 per cent are indigenous and the balance are imported. It is high time that the government have had a long-term perspective plan of making the country entirely self-sufficient in the field of fertilizers. I, therefore, demand through you, Madam, that there should be the setting up of fertilizer plants on a war-footing because in many of the plants which are now coming up, the cost over-runs are there because of the time lag. And still die demand for fertilizers is going up day by day. And I do not know whether we will be able to have self-sufficiency in fertilizers at all. And also the cost of importing fertilizers, you know very well, Madam, involves a huge amount of foreign exchange. And, therefore, I would request that the Ministry-pay attention to this. And also in our public sector fertilizer undertakings, some are not working to their maximum capacity. The capacity utilisation should be properly monitored. Even recently the Prime Minister has drawn attention to die fact of the bad running of the public sector undertakings. And this is one place where with a little bit of more monitoring, you can definitely see that the existing units, wherever they are, can produce more than what they are producing now.

Now, coming to the pricing of the agricultural produce, Madam, recently the name of the Agriculture Prices Commission (APC) has been changed to the Commission for Agricultural Costs and Prices. Mere renaming and gimmicks like this will not work. You have only put the old wine in a new bottle. What is really required is that you should go into the cost of inputs and also see that the farmer gets a remunerative price. In this connection, I would very much like to say one thing. Unfortunately, my good friend, Rao Birendra Singh is ne here; otherwise he would have interjected something. There is this question of wheat versus rice. This wheat lobby is very strong. And with due respect to my friends like Sultan Singhji and others who are sitting here, the wheat lobby is

are sitting here, the wheat lobby is so strong that they always get 20 rupees more than the rice lobby though the cost of production for both|wheat and rice is the same. It has been proved time and again but the APC is not prepared to accept it. Today the minimum price of wheat is Rs. 157 whereas it is only Rs. 137 for rice. We strongly demand that this sort of distinction between wheat and rice should go and a new thinking on this should be there. Incidentally, today your stock of wheat is so much that you have to export five lakh tonnes to Russia, two lakh tonnes to Rumania. And it is because you have got a very good stock of 22 million tonnes of foodgrains in India. While I congratulate you on this record production of 151 million tonnes of foodgrains, at the same time I feel exporting wheat at a price lower than what it costs you to procure here is foolishness. Therefore, T would very much like you to see that some steps are taken to see that while remunerative prices are paid to the farmers, at the same time you do not have to export foodgrains at a loss! I am very happy that the rate of food production in our country is more than that of the rate of growth of the population. This is one thing which has to be said to th* credit of our farmer.

"When once destroyed, can never be supplied." Therefore, everything has to be done for the farmer to see that he gets remunerative prices for his produce.

Now, Madam, thee is a paradox here in India. There is poverty amidst plenty. While the foodgrain buffer stocks are there and you are able to export and arrive at a good rosy picture on the food front, the per capital consumption, on the othe[r] hand, is not going up. Tt is something like 595 grams. And this is not going up. That shows that there are still at least 48 per cent of the people in the country below ihe poverty line who are not able to get any food. On the one hand, we have sufficient foodstocks On the other hand, we are not able to feed the people. Therefore, what is necessary is that you should put purchasing power in the hands of the rural poor and for this you Rural Development Ministry is there and of course good schemes are there like the IRDP, NREP and other programmes. But, unfortunately, as I said in the earlier Bud get speech, adequate budget provisions have not been made for these two schemes. The Finance Minister explained it away saying that because some of the States were busy with elections these Budgets could not be finalised and that proper amounts will be allocated in the next Plan period for these very important programmes which are really to be geared for the rural infrastructure.

Now, I come to another important aspect, namely, the agro-based industries. There should be a proper weightage given for the development of agro-based industries in out country. Unfortunately, T do not know what steps are being taken by the Ministrv on this front. T would like the Minister to elaborate on that.

Now, T come to another important subject under agriculture, namely, fish production. Our coun-try has a coastline of 6,536 kilometres and T am proud to say that mv State, Tamil Nadu, has sot 1.000 kilometres of this coastline. But unfortunately, though we are the largest producer, in the Commonwealth of fish and eighth lar-gest producer in the world, we are not taking adequate steps to see

[Shri R. Ramakrishnan]

that fish production is increased. A small country, a teeny-weeny country, like Taiwan is able to have so many trawlers and their trawlers come to Indian territorial waters and poach there. Now, under the new economic zone of 350 kilometres we can do quite a lot for increasing fish production and become the biggest producer of fish in the world. I would request the Minister to set up the Deep-Sea Fishing Corporation, acquire modern trawlers and see that fish, which is a very valuable protein food, and a cheap food, are within the purchasing power of the poor people. This can be done. You should set up a deep sea fishing corporation and the headquarters of this corporation should be somewhere in Tamil Nadu because of its long coastline.

Now, coming to the rural indebtedness, Madam, there is an old saying that the Tndian farmer is born in debt, is brought up in debt and dies in debt and leaves behind only debts. Today in spite of financial institutions like NABARD and all the regional rural banks and the co-operative societies, you are not still able to give the farmer money for either purchasing rice *or* wheat, or whatever it is, or even for his social requirements. The NABARD loans are given at 13 per cent interest. Whereas you can difinitely see that it is subsidised and give it to him at lesser rate of interest so that the farmer is able to come up.

Madam. T will not take more of your time. T am already able to see the anxiety in your eves. T will just conclude in a few minutes. T want to say that agricultural education is very important. The Ministrv has been doing pood work a"d we have some of the best nelsons in the field of agriculture who have even got world recognition like Dr. M. S. Swaminathan, who, I am proud to say, is from the south, Tamil Nadu, and, at the same time, well, you are having all these universitiess, deemed universities, the Izzatnagar University, the Pantnagar University and in Tamil Nadu, the Agricultural University at Coimbatore. Agricultural education should be imparted to the farmer. It is not enough if our boys and girls go to the colleges and study but this education should go to the root level, to the farmer and he should be educated on modern techniques of crop protection and cultivation. So, it is very important that this education should reach the grass root level. I would request you to see that more steps are taken to see that this education reaches the grass roots level. Now, Madam, before I conclude, I want to say something about the Equine Development Board, as a person closely connected with horses. I do not know whether the hon. Minister knows anything about this Equine Development Board. This Board has been constituted under the chairmanship of the hon. Minister of Agriculture. But whoever planned this Board has obviously done it not out of any intelligent thinking but out of some pressures by some section. The Equine Development Board is for seeing that proper development of equine is there. You have now put in this Board the parage breeders of Haryana. They are having just one or two horses in their parage and these are the representatives who have been out on the Board . There are 5 Turf Authorities of India, Madras, Bombav. Bangalore, Hyderabad and Calcutta and these people do not find any representation on the Board and you are having the so called breeder of Har. yana and such other interests o« the Board. This is very wrong and I

would request me Minister to see that this Board is reconstituted, by giving proper representation to the Turf Authorities who are involved in breeding.

Before I close, I would like to say that under the dynamic leadership of our Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Talaivar M. G. Ramachandran, agricultural base in Tamil Nadu has taken giant strides and steps have been taken by Tamil Nadu Government regarding improvement of the lot of agriculturist and agriculture. We passed an Act, the Minimum Wage Legislation Act for payment of minimum wages to agriculturists and this is being implemented. Some of my friends lake Shri Kalpnath Rai demanded .payment of minimum wages to agriculturists. Tamil Nadu is on the forefront. We are taking steps to give adequate support price ' and remunerative price to the producer for the produce. We are giving fertilizers at subsidised prices to the farmers. We have written off Rs. 210 crores of rural debts in respect of small and marginal farmers. We have introduced oldage pension scheme and we have set up a high-level committee for agriculture and marketing under the Chairmanship * of a person of the rank of a Cabinet Minister. We have also started a scheme for changing the base of rural economy, which is called self-sufficiency programme and all the necessities for the villages, like transport, roads, schools, primary health centres, Hospitals and electricity are being provided. Under the rural electrification scheme, 5.62 lakh huts have been energised and besides that, farmers with less than 5 acres holding get free electricity completely. As you know, for energisation of pump sets in Tamil Nadu, efforts are going on, 288 RS—a on a war tooting ana electricity tor the pump sets is given at a nominal rate—a rate which is not even worth mentioning. So, as far as Tamil Nadu is concerned, we are taking adequate steps and with the help of the Centre and the dynamic Minister like Mr. Buta Singh who is not here unfortunately because he is in hospital, and also his able colleague Mr. Chandrakar, I hope that this Ministry will definitely take the flag of India flying high to greater heights.

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय (बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने अभी कृषि के बारे में बोलने का जो मुझे समय दिया उस के लिए मैं अनुग्रहीत हूं । भारत एक कृषिप्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । उनकी जीविका कृषि पर निर्भर करती है । पैदावार बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाये हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है । 1900 से 1947 तक बढ़ोतरी हुई 0.3 परसेंट, 1950 से 1980 तक कम्पाउंड एनुअल रेट था 2.8 परसेंट । 1983–84 में उत्पादन 1515 लाख मीट्रिक टन था जो कि 1981–82 से 182.4 लाख मीट्रिक टन अधिक था ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) पीठासीन हुए ।]

इस के लिए अनुकूल मौसम के साथ ही इनपुट्स जैसे सिंचाई की सुविधा, अच्छे किस्म के बीजों को उपलब्ध कराना उर्वरकों की मांग को पूरा करना—यह जो हमारी सरकार की सारी नीति रही है उस को अपनाने के कारण हम ने खाद्यान्न के विषय में काफी तरक्की की है। आज उस के परिणामस्वरूप हम ने 151.5 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार करने में सफलता प्राप्त की है । आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न है और हम इस स्थिति में हैं कि उसे बाहर भी भज सकें । पैदावार में वद्धि लाने के लिए

4 P.M.

[श्रीमती मनोरमा पाण्डेय]

जो भी नये-नये कदम उठाये गये हैं जैसे सिंचाई की सुविधाओं में सुधार, क्राप इंश्योरेंस, कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम, सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोआपरेटिव फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्रोग्राम लेकिन आज किसानों की जो खरीदारी की क्षमता है वह इतनी अच्छी नहीं है । उन में रिस्क लेने की जो क्षमता है उस में कमी है । जितनी लागत उन के उत्पादन पर लगती है उस को देखते हुए उन की कीमतों का निर्धारण होना चाहिए । यह अच्छी बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ने एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की जगह एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन की स्थापना की है इस के लिए देखना होगा कि सचमुच में किसानों की जितनी लागत लगती है । अपनी पैदावार में सही मायनों में उन को उस का उतना दाम मिलना चाहिए । इसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किये गये है जिस से उन को उत्पादन में आई आर डी पी के द्वारा मदद दी जाये । लेकन किसानों को जो भी सहायता दी जाती है चाहे वह बैंकों के द्वारा हो या सबसीडी आदि के द्वारा, उन सब के लिए उन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । साथ साथ जो रेट आफ इंटरेस्ट उन को देना पड़ता है वह भी ठीक नहीं है । हालत यह है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोल आफ रूरल रिच इज टाइटनिंग । देहात में डामिन्स आफ रिच पीपुल बढ़ता जा रहा है । एन आर ई पी और मिनिमम नीडस प्रोग्राम जो कि फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और लैंड लेस के लिए बनाया गया है उस के इंप्लीमेंटेशन स्टेज में बैंक किसानों को पूरी तरह से मदद नहीं दे पाते हैं और किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए हमें देखना है कि जिस उद्देश्य से यह कर्ज या सब्सीडी दी जाती है वह उन्हें मिलती है या नहीं । स्माल और मार्जिनल फार्मर्स. 73 परसेंट आफ दि होल्डिंग्स हैं लेकिन सिर्फ 23 परसेंट ही हमारे यहां कल्टीवेबिल एरिया है । इस को बढ़ाने की दिशा में कार्यवाही होनी चाहिए । अभी तक जो भी हम ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया है वह गेहूं की तरफ किया है । लेकिन गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ हमें किसानों को दाल और तिलहन के मामले में भी इंसेंटिव देना चाहिए खास तौर से इस देश के पूर्वी क्षेत्र में जहां पर कि चावल की पैदावार अधिक होती है और होने की गुंजाइश है । वहां पर चावल की पैदावार को बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार ने 51 ब्लाकों को अभी तक सेंट्रल असिस्टेंस के साथ चुना है । लेकिन केवल इतने ही प्रखंडों से काम नहीं होगा । इन प्रखंडों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है उस को हमें बढ़ाना है । इसी तरह से दाल और तिलहन और कपास और जूट और गन्ने की खेती में ह्रास हुआ है । गन्ने की खेती का तो यह हाल है कि बिहार के उत्तरी जिलों के किसान तो सोचने लगे हैं कि वे गन्ना खेत में लगाया ही न करें । क्योंकि जो इंसेंटिव आप गेहूं और चावल के लिये देते हैं वह गन्ने के किसानों को नहीं मिल पाता है । लगभग 1300 करोड़ रुपये की दाल और तिलहन हम विदेशों से मंगाते हैं । अतः दाल और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को उतना ही इंसेंटिव देना चाहिये जितना कि चावल और गेहूं के लिये हम देते हैं ।

हमारा रिसर्च अभी तक जितना भी हुआ है वह बहुत स्लो है और अनरिम्युनरेटिव है । वास्तव में भारत ही ऐसा देश है जहां पर सिंचाई के लिये बहुत क्षमता है और उस की संभावनयें हैं । हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम में भी उस को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । फिर भी हमारी जो उपलब्ध सिंचाई की क्षमता है, जो हमारे साधन हैं उन को हम पूरी तरह से एक्सप्लायट नहीं कर पाते हैं । हमारे यहां वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है । अभी पूरे देश में 40 हजार मिलियन हेक्टर अंडरग्राउन्ड वाटर की क्षमता हमारे देश में है जिस में बिहार बंगाल आदि राज्यों में अन्डरग्राउन्ड वाटर को एक्सप्लायट करने की दिशा में कार्यवाही होनी चाहिए । क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं

वह उतने कामयाब नहीं हो सके हैं हम को अंडरग्राउन्ड वाटर को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए । बिहार प्रान्त में 105 मिलियन टन आज पैदावार की स्थिति है और उस को बढाने के लिये हमें इनपुट्स को बढ़ाना चाहिए, मार्डन टेक्नोलाजी को और अंडरग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल को एक्सप्लायट करना चाहिए क्योंकि हमारी जो उपलब्धि है और जो एचीवमेंट्स हैं उन में काफी डिफरेंस है। उपाध्यक्ष महोदय हमें रिसर्च करने के लिये प्रत्येक जिले में एक अग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना पर भी जोर देना चाहिये ताकि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी गांवों में जाकर किसानों को समझायें उनको बतायें कि माडर्न टेक्नालाजी का किस तरह से सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है ।

जहां तक कोआपरेटिव सैक्टर में जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं उनका प्रश्न है वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं । अतः अधिक से अधिक कोआपरेटिव सैक्टर में फर्टिलाइजर प्लांटों की स्थापना पर भी जोर देना चाहिये ।

तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी, वह यह है कि किसानों को जो ऋण दिये जाते हैं, उनके लिये उनके पास पास-बुक होनी चाहिये जिसमें उनकी जमीन का लेखा-जोखा हो, जिसके आधार पर उनको ऋण या सबसिडी दी जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ, अब तक सरकार ने इस दिशा में जो प्रगति की है उसकी सराहना करते हुये मैं आपके माध्यम से सरकार को और आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि का महत्व बहुत ही अधिक है जैसा हमारे काफी माननीय सदस्यों ने कहा है । अभी भी राष्ट्रीय आमदनी का 38 प्रतिशत कृषि से उपलब्ध होता है और दूसरी तरफ जितने भी कृषि पर आधारित उद्योग हैं, उन्हें कच्चे माल के लिये इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन कृषि के बारे में सरकार की नीति बिल्कुल उपेक्षा की नीति है । सरकार ने कृषि को देश के मुट्ठी भर पूजीपतियों के लिए चरागाह बना दिया है और सरकार की नीति से किसानों का सर्वहाराकरण शुरू हो गया है । इसलिये इन नीतियों पर सही ढंग से विचार करना चाहिये ताकि कृषि को ठीक ढंग से विकसित किया जा सके ।

महोदय सरकार को इस बात पर काफी गर्व है कि उसने देश में 151 मिलियन टन अन्न का उत्पादन किया । उत्पादन होना एक बात है लेकिन देश की जनता को अन्न की प्राप्ति होना दूसरी बात है । 1979 में जहां प्रति व्यक्ति को प्रति दिन 474 ग्राम अनाज प्राप्त होता था, आज 151 मिलियन टन अनाज पैदा होने के बाद भी लोगों को महज 442 ग्राम अनाज प्रति दिन प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है । इसलिये गर्व तो किया जा सकता है उत्पादन पर, लेकिन जब उसका लाभ उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखते हैं तो मालूम होता है कि देश में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत कम होती चली जा रही है । दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारे देश के अंदर 154 मिलियन हैक्टेयर में खेती होती है और उत्पादन हम 151 मिलियन टन करते हैं । चीन में 100 मिलियन हैक्टेयर में खेती होती है और उनका उत्पादन 400 मिलियन टन है । इसलिये इससे यह जाहिर होता है कि हमारे देश के अन्दर अन्न का उत्पादन प्रति हैक्टेयर जो हमारी तरह से अर्द्ध-विकसित देश हैं उससे भी कम है ।

महोदय, दूसरी चिन्ताजनक बात यह है कि कृषि में जिस गति से देश में प्रगति होनी चाहिये उसके मुताबिक प्रगति नहीं हुई । पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन हम 60 से 70 तक और 80 से 90 तक की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विकास की गति को देखते हैं तो ह्रास नजर आता है । 60 और 70 में कृषि का विकास महज 2.6 प्रतिशत हुआ । 70 और 80 में 2.4 प्रतिशत हुआ । 80 और 85 के बीच कृषि में विकास 2.6 प्रतिशत है । जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर लक्ष्य रखा गया था कि कृषि का विकास 3.6 प्रतिशत के हिसाब से होगा । हमारे देश में जनसंख्या का विकास कितना है 2.2 प्रतिशत । ऐसी अवस्था में हमको देखने को मिलता यह है कि 6 पंचवर्षीय योजनाओं के

[श्री सूरज प्रसाद]

बाद भी कृषि के विकास की गति वही है जो हमारे देश में जनसंख्या के विकास की गति है । ऐसी स्थिति में देश में अधिक अन्न उपलब्ध हो जाना असंभव सी बात है । सरकार का यह भी कहना है कि हमने इतना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है कि हम किसी भी चपेट का सामना कर सकते हैं । लेकिन यह बात देखने से साबित नहीं होती । 1982 में अकाल पड़ा इसमें अन्न का उत्पादन कितना हुआ । 126 मिलियन टन और 1981 में 134 मिलियन टन का उत्पादन हुआ । तो क्या हमारा लक्ष्य पूरा हुआ । क्या हमने अपने लक्ष्य से अधिक अन्न का उत्पादन किया । अगर मौसम खराब हो गया, बारिश नहीं हुई तो पैदावार घटती है । हमारे देश के अन्दर कृषि पर मौसम का असर पड़ता है ।

हमें खेती में नेगेटिव फीचर भी देखने होंगे । जो खेती में नेगेटिव फीचर देखने को हमें मिलता है वह यह है कि हमारी खेती में असामान्य विकास है । सामान्य विकास नहीं है । क्षेत्रीय असमानता है । क्षेत्रीय असमानता की जब बात बोलता हूं तो इसका अर्थ यह है कि देश के विभिन्न राज्यों में कृषि में सामान्य विकास नहीं होता । जब अंग्रेज अपने देश में राज्य करते थे तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों को विकास के लिये चुना। पंजाब को चुना हरियाणा को चुना उसने पश्चिमी यू0 पी0 को चुना और उसने कृष्णा नदी के इलाके को चुना । इन इलाकों में उन्होंने कृषि का विकास किया और कुछ कामर्शियल क्राप्स के लिये भी इलाकों को चुना । उन्होंने वहां पर विकास किया और कुछ पैसे भी इन्वेस्ट किये । जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो सरकार ने यह कहा था कि कृषि के विकास में असमानता है । इस असमानता को दूर करने के लिये कोशिश की जानी चाहिये । पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान तो कुछ हुआ लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के दरमियान सरकार ने एरिया डवलोपमेंट की योजना सामने रख दी । सरकार ने इन क्षेत्रों को विकास के लिये चुना । पंजाब को चुना, हरियाणा को चुना, पूर्वी यू0 पी0 को चुना, मद्रास का कुछ हिस्सा चुना, कृष्णा नदी का, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में कृषि के विकास की दिशा में सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया । दूसरे राज्य जैसे पश्चिमी और पूर्वी राज्य हैं, बिहार है, बंगाल है, असम है, मणिपुर है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और कुछ पूर्वी यू० पी० है । ये कुछ इलाके हैं जहां कृषि का विकास छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नगण्य है । इतना ही नहीं क्षेत्रीय असमानता के साथ-साथ क्राप के विकास में भी असमानता है । अगर कहीं कुछ विकास हुआ तो केवल गेहूं की पैदावार में और थोड़ा सा चावल में । इसमें थोड़ी तरक्की हुई इसलिये इसे प्रशंसनीय कहा जा सकता है । लेकिन दूसरे बहुत से क्राप्स हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसमें विकास नगण्य हैं । 69 और 75 के बीच में देश ज्वार और बाजरा के विकास में नैगेटिव रहा है । इतना ही नहीं देश के अन्दर तिलहन और दलहन का विकास 10 मिल्यिन टन के दरमियान रहा । इसमें भी गतिरोध पैदा हो गया है ।

समय आपने बहुत ही कम हमें दिया । लेकिन मैं कुछ प्रश्नों को रखना चाहता हूं इसलिये थोड़ा सा समय और देने का कष्ट करेंगे । मेरा कहना यह है कि इसी तरह से कपास और जूट के प्रोडक्शन में स्टेग-नेशन आई है, फिगर्स देना नहीं चाहता । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारत की कृषि हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के लिये चरगाह बन गई है । किसानों को उचित मूल्य सरकार नहीं दे पाती । इस साल सरकार ने इकनोमिक रिव्यू प्रस्तुत किया है । उसमें यह बताया गया है कि औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के मूल्यों में 6 प्रतिशत का अन्तर है । इसके लिये सरकार ने कहा कि चीजों के होलसेल प्राइस इंडैक्स में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । लेकिन किसकी कीमत पर ? कृषि उत्पादन की कीमत पर । इस सम्बन्ध में एक दो फीगर्स में इसके सबूत में देना चाहूगा । फल और सब्जियों में सन् 1984–85 में 24 प्रतिशत की कमी हुई है । कपास की कीमत में 31.7 प्रतिशत की कमी हुई है । यह सन् 1983–84 क तुलना में है । जूट में 18 प्रतिशत की कमी हुई है । चावल में 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई है । अगर मैं होलसेल प्राइस इंडैक्स को लूं तो पता चलेगा कि राइस का होलसेल प्राइस सन् 1983–84 में 276 था तो सन् 1984–86 में 282 है । व्हीट का सन् 1983–84 का प्राइस इंडैक्स 219

था तो सन् 1984–85 का 210 है। इस प्रकार से दो ये ऐसी फसलें हैं जिनका किसान उत्पादन करता है। दोनों फसलों में लूटने की तरफ इस बार कोशिश हुई है। आप जानते हैं कि यू० पी० के अन्दर इस साल आलू का उत्पादन हुआ है। आलू की कीमत 25) रु० क्विंटल है। महोदय, केरल से हमारे पास लोग आए हैं। उन्होंने बताया है कि इस साल कोकोनट में भारी गिरावट आई है। उसका प्राइस गिरा है। कोकोनट का आयात किया जा रहा है। कोकोनट के तेल और कच्चे कोकोनट का आयात किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि उसके प्राइस में गिरावट आई है। इस बार हमने देखा कि हिंदुस्तान में कृषि लूटने का एक जरिया बन गया है। मुट्ठी भर सेठ-साहूकार लोग किसानों को लूटने पर तुले हुये हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गन्ने के प्रति सरकार की गलत नीति के कारण गन्ने की पैदावार में गिरावट आई है। पहले हमारे देश में 83 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था, लेकिन अब 62 लाख टन हुआ है। इसके चलते विदेशों में चीनी का आयात करना पड़ रहा है। इसके दो कारण हैं। सरकार ने किसानों को गन्ने की उचित कीमत नहीं दी और चीनी मिल-मालिकों ने बकाया की जिस राशि का भुगतान करना था उसका भुगतान नहीं किया। इसके चलते किसानों के द्वारा गन्ने के उत्पादन में उपेक्षा हुई, जिसके चलते इस तरह की बात हो रही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस साल सरकार न जो कृषि का बजट प्रस्तुत किया है उसमें कृषि के प्रति उपेक्षा बरती गई है। सन 1984–85 में 8862 करोड़ रूपयों का बजट था। इस साल यह 2702 करोड़ रूपयों का है। सरकार ने इस बजट में व्हील में, पशुपालन में, मीट उत्पादन में दूध उत्पादन में, सिंचाई और बाढ नियंत्रण के लिये जो प्रबन्ध किया है वह बहुत ही कम है। इनके लिये आपको बजट में अधिक से अधिक पैसा देना चाहिये था। गत वर्ष की तुलना में इस साल जो प्रावधान किया गया है वह बहुत ही कम है। उस तरह से यहां पर कृषि बीमें की बहुत चर्चा की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने रुपये को आपने कृषि बीमे के लिये बजट मे प्रावधान किया है? सिर्फ चार करोड़ रूपया और सिर्फ सौ जिलों में आप इसको कर पायेंगे। सीमान्त किसानों के विकास का बात भी कही जाती है। लेकिन इस मद में इस साल के बजट में कटौती की गई है। गत वर्ष इसके लिये 57.7 करोड़ का बजट था, इस वर्ष सिर्फ 96 करोड़ का बजट है। अन्त में यह कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर कृषि का विकास करना है तो 3–4 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये। सरकार ने भूमि सुधार की उपेक्षा की है। सरकार ने 215 लाख एकड़ जमीन हदबंदी के लिये अर्जित करनी थी और प्लानिंग कमीशन की इस प्रकार की योजना थी आपने सिर्फ 42 लाख एकड़ ही अर्जित की। बाकी 20 लाख एकड़ पर कब्जा किया। इस प्रकार से सरकार ने भूमि सुधारो की बिल्कुल उपेक्षा की है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते है कि किसानों को कर्जों की जरूरत होती है। किसानों को कुल कितना कर्जा बैंकों से मिला है? बैंकों से सिर्फ 13 प्रतिशत किसान को कृषि कर्ज के रूप में दिया गया है। इसके अलावा उससे सूद का रेट भी बहुत हाई है। इसलिये मैं सरकार से। कहना चाहिता हूं कि 6 प्रतिशत दर पर किसानों का कर्जा दिया जाना चाहिये

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : समाप्त कीजिये।

श्री सूरज प्रसाद : सरकार को देहातों में माडर्न टेक्नालाजी लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं और इस क्षेत्र में जो असंतुलन है उसको दूर करने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं। केरल के जो किसान प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर आये हैं, कोकोनट के बारे में, जो आज मिले हैं, उनकी कुछ समस्यायें हैं, बीमारी उन समस्याओं के समाधान की तरफ सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि कृषि के विकास की दिशा में सही दिशा लाई जा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Shrimati Monika Das. Not present. Shri Adinarayana Reddy. Not present.

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जितने मेरे साथी, आनरेबल मेम्बर्स इस हाउस में बोले हैं सभी ने एक बात पर जोर दिया कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में अनाज की पैदवार पिछले दिनों में बहुत बढ़ी है लेकिन जितने भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिये हैं, जितनी जमीन और पानी हमारे पास है, उसके मुताबिक यह पैदावार कुछ भी नहीं है। अगर इन सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लाइट किया जाय, पूरी तरह से प्रयोग में लाया जाय तो हमारा देश तमाम दुनियां में सबसे बड़ा अन्न का भंडार बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वे सारे रिसोर्सेज भी प्रयोग में नहीं आये। हमारे देश में अभी भी ड्राउट आता है और फ्लड्स भी आते हैं। जब डाउट और फ्लड दोनों आते हैं तो उसके माने यह हैं कि रिसोर्सेज का ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है। अगर रिसोर्सेज का प्रयोग ठीक से हो जाय तो वह पानी जो फ्लड में जाता है वह दौलत पैदा कर सकता है। श्रीमन कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। अच्छा बीज, अच्छी खाद और अच्छा टैक्नालाजी तथा पानी। हमारे देश अभी तक यह हालत है कि सीड कारपोरेशन अभी तक गांवों में नहीं पहुंचा है। मुझे पता है कुछ जो किसान हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वह कई कई दिनों तक यूनिवर्सिटीज के दरवाजे पीटते है, यहां पूसा में खड़े रहते हैं और दूसरी दूसरी जगहों पर बीज तलाश करते है। सीड कारपोरेशन अभी तक गांवों में नहीं पहुंचा और न वहां सीड का देने का इंतजाम है। सीड का सर्टीफिकेशन भी नहीं हो रहा है। कई आदमी इल्लीगली, गलत बीज बेचते हैं कोई उन पर कन्ट्रोल नहीं है। तो मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सीड कारपोरेशन हर गांव पहुंचे और अच्छे से अच्छे सीड उसी गांव में पैदा करवाये और उसे गांव में ही प्रोक्योर करे और फिर उसका वितरण करें, ठीक तरीके पर, ताकि उसके ऊपर लागत भी ज्यादा न आये तथा किसानों को अच्छा बीज मिल सके। कृषि के साथ उसके जोड़ के बहुत से धंधे हैं। कृषि में, एनिमल हजबेंडरी, डेरी डेवलपमेन्ट पाल्ट्री फार्म, फिशरीज और फारेस्ट्री ये सारी चीजें भी कृषि का भाग हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य से एक चीज जो आज मैं महसूस करता हूं वह यह है कि एनिमल ब्रीड बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं हरियाणा से आता हूं। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा होता था। तो गांवों में हम बहुत सारी ऐसी भैंसें देखते थे, भूरा नस्ल की जो कि 20–20 22–22 किलो दूध देती थी। उस जमाने में नाप सेर में चलता था और वे डेढ़ सेर तक घी देती थी। ये भैंसे आज हम सारे गांवों में घूमकर देख लें तो 12 किलो दूध देने वाली भैंस भी कई कई जगह तलाश करने से ही मिलती है। उसका ड्राई सीजन...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : (उत्तर प्रदेश) : गिर गई या बढ़ गई ?

श्री सुलतान सिंह : यानी इससे कमी आई है। तलाश करने से भी कोई एक भैंस 12 किलो दूध की मिलती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यानी इसमें गिरावट आई है।

श्री सुलतान सिंह : गिरावट आई है और हालत यह है कि आप सभी देखें कि उसका ड्राई सीजन भैंस का आज कितना ज्यादा बढ़ गया है। कोई भैंस शायद ही होगी जो पूरा एक ब्यांत मार के न बहती है। इसका मतलब उसका लांगेस्ट पीरियड रहता है ड्राई में। उसकी वजह क्या है ? वर्मा जी आते हैं, कल्पनाथ

जी आते हैं, विकल साहब आते हैं सब गांव के आदमी हैं आज किसी भी गांव के पास अच्छा बुल नहीं रहा, वही कटड़ा जो बुगियों में ले कर चलते हैं उन्हीं से भैंस का गर्भाधान कराया जाता है और सरकार ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और इस प्रकार से हमारे देश की जो बेस्ट ब्रीड है वह खत्म हो रही है। मिनिस्टर साहब को पता है कि मूरा नस्सल के बुल वियतनाम, कोरिया, बुलगारिया में गये और आज 10–10 लाख रुपये का बुल खरीदने को तैयार हैं। यूरोपीयन कंट्रीज क्योंकि वहां गाय के दूध में फैट कंटेंट्स कम हैं और मूरा नस्ल में फैट कंटेंट्स ज्यादा हैं । वह हमारी भैंस को ले जा कर के अपनी नस्सल बनाने लगे हैं और हमारी नस्ल जो इतनी खूबसूरत और बढ़िया थी वह हम अपने यहां खत्म करने लग रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । मैं गलती नहीं करता तो सभी मैम्बर साहेबान जानते हैं कि 10 हजार पशु के पीछे एक डाक्टर की बात तो छोड़िये एक वेटरनेरी कम्पाउंडर भी नहीं हैं । आप सर्वे कर के देखिये एक वेटरनेरी कम्पाउंडर भी 10 हजार पशुओं के पीछे नहीं हैं । डाक्टर की बात छोड़िये । डाक्टर तो कई लाख पशुओं के पीछे एक डाक्टर नहीं मिलता है । हमारे यहां एक गांव की आबादी अगर पांच हजार है तो उस गांव में पशु भी पांच पांच हजार की आबादी में कोई पशु अस्पताल नहीं है कोई वहां पर वेटरनेरी कम्पाउंडर भी नहीं हैं डाक्टर की बात तो छोड़िये । इसमें मैं समझ नहीं पाया कि सरकार को वेटरनेरी कम्पाउंडर पैदा करने में क्या दिक्कत है ? स्टाक असिस्टेंट पैदा करने में क्या दिक्कत है ? हिसार यूनीवर्सिटी को हम देखते हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू) पीठासीन हुए]

हमारे हरियाणा की सब से बड़ी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी है । मुश्किल से 60 स्टाक असिस्टेंट पैदा करती होगी जबकि हमारे यहां 6500 के करीब गांव हैं । हम कितने साल में एक वेटरनेरी कम्पाउंडर या स्टाक असिस्टेंट गांव तक भेज पाएंगे और वेटरनेरी डाक्टर की बात ही छोड़िये । एक तो हमारा जो एनीमल ब्रीड है वह खत्म होता चला जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है । तीसरी बात हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट भी एग्रीकल्चर का एक अंग है । गांव में आज हमारे पास जोत कम होती चली जा रही है, जमीन भी कम होती चली जा रही है । अगर हम अपने खेत के अन्दर दो अमरूद के पेड़ लगा दें और एक बेर का पेड़ लगा दें, 10 पपीते के पेड़ लगा दें तो हमारी खुराक में जो कमी आई है न्यूट्रिशन में कमी आई है वह पूरी हो सकती है यह हमारे बच्चों को मिल सकता है इससे दूध की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको कोई गांव का किसान जानता ही नहीं है कि हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट भी करता है । एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आप सर्वे कराईए और देखिए कि हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितनी नर्सरीज बना रखी हैं । प्राइवेट नर्सरीज भी बनी हुई हैं । उनको वह चेक भी करते हैं या नहीं । लोगों को ठगा जाता है। हम प्राइवेट नर्सरी से अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो कहेंगे कि इलाहाबाद का है । उस पर चार साल तक हम मेहनत करेंगे उस पर इतना अमरूद मुश्किल से आएगा । हम प्राइवेट नर्सरी से बेर का पेड़ लगाएंगे कहेंगे कि यह शानदार गोल बेर है और जब फल आता है तो झाड़ का बेर नजर आता है । तो आप हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट में चेक करें कि उन्होंने कितनी नर्सरीज बनाई हैं और लोगों ने जो प्राइवेट नर्सरीज बना रखी हैं उनको हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट कितना चेक करता है, सर्टिफिकेट भी देता है कि नहीं कि आपसे एप्रूव्ड हैं या नहीं। जो प्राइवेट नर्सरी चलाने वाले हैं उनको प्रापर ट्रेनिंग भी आपने दी है कि नहीं ताकि आपका हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट ठीक से काम करे तभी किसान की मदद हो सकती है । कम से कम और कहीं नहीं तो वह अपने बच्चों को कुछ थोड़ी सी डाइट बढ़ाकर दे सकता है, फ्रूट्स के रूप में एक एक या दो दो पेड़ लगाकर । मैं और किसकी बात बताऊं । हमने खुद पपीते के पेड़ लगा दिये, कई साल हो गये पपीता

[श्री सुलतान सिंह]

नहीं लगा । हमने पूछा किपपीते के पेड़ लगाये हैं फल नहीं आता तो एक दिन हार्टीकल्चर वालों ने कहा कि इसमें तो मेल और फीमल दोनों होने चाहिए । आप बताइये कि गांव के किसान को कैसे पता लगे । वह तो गाय या भैंस में मेल फीमेल की तलाश कर सकता है, इन्सान में भी पता लगा सकता है मेल फीमेल का लेकिन पपीते के पेड़ के लिए कैसे पता लगाये कि इसमें कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है । तो ट्रेनिंग होनी चाहिए । आप के गांव के किसानों को ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देना चाहिए । इसी तरीके से ...

(व्यवधान)

SHRI R. RAMAKRISHNAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, on a point of order. There is not even one Cabinet Minister in this House. The Government should not take the proceedings of this House lightly. We can understand the Cabinet Minister, Mr. Buta Singh, not being here because he is sick. But at least some Cabinet Minister on roster duty should be present. They cannot take the Rajya Sabha lightly.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): I also support Mr. Ramakrishnan. We are discussing a vital subject like agriculture. This clearly indicates the attitude of the Government towards this subject. We our strong protest against it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Mr. Minister, please inform the Government.

श्री सुलतान सिंह : इस बात को जानकर खुशी है कि 3 मंत्री यहां बैठे हैं **(व्यवधान)** मंत्री जी अगर जाकर... **(व्यवधान)**... पीछे बैठ जायें.... **(व्यवधान)** फ्रंट पर रहना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं है कि 5 मंत्री हाउस में मौजूद हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस बहस का जवाब भी देने के लिए मंत्री महोदय बैठे हैं ।

इसी प्रकार डेरी डेवलपमेंट का काम है । आप हैरान होंगे कि दिल्ली के आस पास कई चिलिंग प्लांट लगाए गये हैं । दिल्ली का 40–50 मील की रेडियस में डेरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दूध को इकट्ठा करके, चिल्ड करके दिल्ली में बेचने के लिए चिलिंग प्लांट्स लगाए हैं । मैं अपनी आंखों से देखता हूं और आपको पाजिटिव नाम बता सकता हूं । खरखोदा में है, सोनीपत में है, बहादुरगढ़ में है और सांपला में हैं । आप वहां जाकर उन चिलिंग प्लांट्स को देखें, वहां दूध नहीं आता, दीवारें, गिर रही हैं, वहां पर कैटल खड़े रहते हैं, इतनी कीमती मशीनरी लगायी, इतनी अच्छी तरह से चिलिंग प्लांट्स बनाये लेकिन कोई प्रयोग नहीं हो रहा है और इसका रीजन क्या है ? कि वे लोग तो गये चिलिंग प्लांट लगाये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लेकिन कहीं कहते हैं कि यह हरियाणा डेरी डेवलपमेंट के पास जायेगा, कभी कहते हैं इनके पास तो इस डिसिजन लेने में हमारा सारा इन्वेस्टमेंट बरबाद होता चला जा रहा है । यही नहीं आप देखें कि हमारे कितने मिल्क प्लांट्स हैं । मैं गलती नहीं करता तो पूरी कैपेसिटी के मुताबिक वे मिल्क प्लांट नहीं चल रहे हैं । बेशुमार इन्वेस्टमेंट की है, बाहर से लोन आया है, वर्ल्ड बैंक से भी आया है लेकिन इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये मिल्क प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन यह हैकि दूध की पैदावार घटती चली आ रही है और दूध के लिए पूरा पैसा भी नहीं मिलता है.... **(व्यवधान)** इसके अलावा जो आज एक सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है । सरकारी कर्मचारी उसके भी वेतन का एक सिस्टम है, वह प्राइस इंडेक्स के साथ-साथ है । इंडस्ट्रियल गुडज का भी प्राइस इंडेक्स के साथ-साथ उसकी कीमत अन्दाजी होती है । लेकिन दुर्भाग्य से एग्रीकल्चर्ल की जो कीमत-अंदाजी होती है वह प्राइस इंडैक्स के लैवल के साथ-साथ नहीं चलती । अगर प्राइस इंडेक्स के लेवल के साथ-साथ उसका उतार-चढ़ाव आये तो गांव के किसान को एतराज नहीं होगा । मैं यह भी जानता हूं कि अगर एग्रीकल्चर्ल प्रोडक्शन की कीमत बहुत बढ़ती चली गई तो कन्ज्यूमर भी मर जायेगा ।

इसलिए मैं एक बात सरकार से चाहता हूं कि अगर सरकार दिल से और ईमानदारी से चाहे तो एग्रीकल्चर्ल प्रोडक्शन की कास्ट आफ प्रोडक्शन घट सकती है और वह कास्ट आफ प्रोडक्शन अगर आप घटना चाहें तो मैं आपको फार्मूला देने को तैयार हूं । अगर कोई माने तो ? वह कैसे ? आज दस एकड़ का आदमी, किसान कोई फोर्ड ट्रैक्टर खरीदे तो 90 हजार रुपये उसकी कीमत है। 14 परसेंट उस पर सूद है । फिर उसके साथ-साथ डैप्रीसिएशन है । 10 एकड़ का मालिक आज तीन हजार रुपये महीना डैप्रीसिएशन और सूद अदा करे तो यह उसकी रीच के बाहर है । जब सरकार भी अपने कर्मचारियों को तीन-तीन हजार रुपये तनख्वाह देने में आना-कानी करती है तो दस एकड़ का किसान कोई देर कर सकता है क्या, तीन हजार रुपये महीना उसका सूद दे और डैप्रीसिएशन आए । आपने कार पैदा कर दी सस्ती और छोटी । लेकिन अभी तक आपने ट्रैक्टर पैदा नहीं किया छोटा और सस्ता ? आज वैस्टर्न यू० पी० और पंजाब के अन्दर और राजस्थान में बिजली के बैगर हा-हाकार है । मैं कहता हूं कि रशियन ट्रैक्टर आता था डी-14 हम 9 हजार रुपये का ट्रैक्टर लाते थे। वह हमारे खेत का ट्यूबवैल भी चलाता था और प्लाऊ भी साथ-साथ करता था । उससे थ्रेशिंग भी करते थे, खेत के अन्दर उससे वाही भी करते थे और ट्यूबवैल भी चलाते थे और उससे तेल का खर्चा भी कम था । जब आप दुनिया भर के लोगों के लिए इतनी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसान के लिए डीटी–14 क्यों नहीं इंपोर्ट किया जाए ?

एक माननीय सदस्य : या देश में ही बनावें ?

श्री सुलतान सिंह : वह तो सेकण्डरी बात है । इमीडिएट बात यह है कि अगर आप डीटी–14 ट्रैक्टर इंपोर्ट कर दें तो हमारा बिजली का मसला भी हल हो सकता है, हम ट्यूबवैल भी चला सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन की कीमत भी कम हो सकती है, क्योंकि छोटी जोत हमारे पास है। होल्डिंग हमारी कम होती जा रही है । हर किसान छोटे ट्रैक्टर को खरीदने की शक्ति रख सकता है । इसलिए कॉस्ट आफ प्रोडक्शन आप घटाना चाहें तो ऐसे फार्मूले से वह घट सकती है । इसके अलावा एग्रीकल्चर्ल इंजीनियरिंग में हम बिल्कुल फेल हैं । हर साल हजारों आदमियों के हाथ जाते रहते हैं थ्रेशरों में आ करके । अगर किसी कारखाने में एक आदमी का हाथ चला जाए या बायु चला जाए तो उसे कारखाने का मालिक देता है, पैसे लिए जा हैं। लेकिन यहां हजारों-हजार किसान हैंडीकप्ड हो जाते हैं, अपने हाथ दे बैठते हैं, लेकिन आपका एग्रीकल्चर्ल इंजीनियरिंग सोया पड़ा है । वह क्यों नहीं ऐसा थ्रेशर पैदा करते जिससे कि किसान का जिसमें बच जाए और काम पूरा करे । वह क्यों नहीं ऐसी मशीन पैदा करते कि मशीन के ऊपर लोड कम आये और आसानी से वह चल जाए । तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए थोड़े समय में तीन-चार बात ही कहता हूं । आप किसी दिन किसी गांव में चलें, एक गांव में आपको सब चीज मिल जायेंगी । एक ही गांव में आपको एनीमल हसबैंड्री का क्या काम है, उसका पता चल जायेगा, हार्टीकल्चर क्या काम कर रहा है उसका पता लग जायेगा, एग्रीकल्चर्ल इंजीनियरिंग क्या काम करता है, उससे आपको पता चल जायेगा और कास्ट आफ् प्रोडक्शन क्या बढ़ रहा है, उससे भी आपको पता लग जायेगा ? हमारी डे बाई डे नसल जो गिरती जा रही है। मूरा नसल और दूसरी नसलें क्यों गिरती जा रही हैं। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कुछ चीजें कंपसलरी हों । इस गांव में वेटनरी डाक्टर आपका शंतिया हो, अच्छा बुल हर गांव में रहे । जब आपके पास गांव में पढ़े-लिखे बेरोजगार, बेकार आदमी हैं, तो आप उनको दो-तीन साल की एनीमल साइड में ट्रेनिंग दीजिए और गांव में एक आदमी की ड्यूटी लगा दें । एक कीमती नस्ल वेस्ट जा रही है। सिर्फ गांव में ज्ञान की जरूरत है ।

इसलिए आप मेहरबानी करके हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियर को और आपका एनीमल हस्बेंडरी जो है, उस सबको टाइट करें और फिर देखें कि यह इंटीग्रेट रूरल डवलपमेंट जो स्कीम है या आपकी एन० आर०पी० स्कीम है, वह सारी की सारी स्कीम कामयाब होंगी ।

[श्री सुल्तान सिंह]

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि महीने में एक दिन मेहरबानी करके मिनिस्टर जाकर गांव में देखें, वहां सर्वे करें। जो दिल्ली के नजदीक गांव हैं, वहां आप चल दें, वहां सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके जो एक्सपर्ट हैं, उनको साथ ले लीजिए और अपने साथ बैठाइए। एक गांव से आपको सारे हिन्दुस्तान का नक्शा नजर आ जाएगा।

तो मेहरबानी करके इन बातों की तरफ ध्यान दें ताकि यह देश बचे और किसान की तरक्की हो। आपने जो क्राप इंसोरेंस की स्कीम लागू की है, उससे किसानों में बहुत उत्साह है और उसके लिए वह बहुत खुश हैं। लेकिन स्कीम इंपलीमेंटेशन पर भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि स्कीम तो आ जाती है अच्छी, लेकिन बाद में उसमें जाकर ब्लेक-मेलिंग शुरू हो जाती है। उससे भी हमको बच के रहना है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

STATEMENT BY MINISTER

Increase in the Swantantrata Sainik Sanunan Pension

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs will make a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I am glad to announce in the House that the Government have decided to increase the quantum of monthly pension admissible to freedom fighters and the widows of the deceased freedom fighters under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme to Rs. 5001- per month. The increased rates of pension will be effective from 1st June, 1985.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT—contd.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। देश के किसान ने कड़ा परिश्रम कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्म-निर्भर बना दिया है। गत् दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दो वर्षों में 6.6 प्रतिशत खाद्यान्नों के भाव में गिरावट आई है। पिछले वर्ष गेहूं और चावल के उत्पादन में देश में कीर्तिमान स्थापित हुआ। लेकिन गेहूं के मूल्य में 3.8 प्रतिशत और चावल के मूल्य में 5.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे मान्यवर, जाहिर है कि किसान जब अधिक पैदा करता है, और अधिक पैदा करने के लिए बीज पर, खाद पर, पानी पर, कीटनाशक दवाइयों पर और मजदूरी अधिक व्यय करता है और अधिक उत्पादन करता है, उसके दुर्भाग्य से कृषि-उत्पाद का मूल्य गिरता है और अलाभकर होता है। इसके बिल्कुल विपरीत उद्योगों में जब उत्पादन बढ़ता है, तो उद्योगपतियों का पौ-बारह होता है।

मान्यवर, मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि किसान ऐसा अभागा है कि जब वह अपने खेत पर जाता है, उसका उत्पादन बहुत उत्तम और बढ़िया होता है, तो अपनी फसल को देखकर खुश होता है। लेकिन फसल जब मण्डी में लेकर जाता है, तो भाव को देखकर रोता है और जब उसकी पैदावार गिरती है, तो अपने खेत की फसल को देखकर रोता है।

अच्छी फसल होती है, भाव गिरता है तब रोता है, खराब उत्पादन हो तो खेत की मेंड़ पर खड़ा होकर रोता है। उस अभागे के लिए दोनों हालत में रोना है